मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/05256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

# जगत विज़न

वर्ष : 26 अंक : 4

दिसंबर 2025

## बिहार चुनाव

# तिकड़ी की तिकड़म

## लोकतंत्र नहीं नमोतन्त्र है ये

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

*निर्भीक पत्रकारिता*


**संपादक** विजया पाठक
**कार्यकारी संपादक** समता पाठक
**पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ** अमित राय



**सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय**

**भोपाल**

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

**छत्तीसगढ़**

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर



**स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक**

विजया पाठक द्वारा जगत प्रिंटर्स पब्लिशर्स, खसरा नं. 1/1/6 अमरावद खुर्द बरखेड़ा पठानी, फंदा भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

***E-mail : jagat.vision@gmail.com***
***Website: www.jagatvision.co.in***



**मासिक द्विभाषी पत्रिका** **वर्ष 26 अंक 04 दिसम्बर 2025**

बिहार चुनाव

# तिकड़ी की तिकड़म

## लोकतंत्र नहीं नमोतन्त्र है ये

**(पृष्ठ क्र.-6)**


■ छत्तीसगढ़ में मोस्ट वान्टेड नक्सली हिडमा के एनकाउंटर से उठे सवाल ..30
■ दृढ़ संकल्प से ही शराबबंदी संभव ! ....................................39
■ प्रदूषण का समाधान सामुदायिक सहभागिता एवं सरकारी ............... 42
■ धामी सरकार के तीन वर्ष : निर्णायक फैसलों की मिसाल ............... 44
और जनता के हित में उठाए ठोस कदम
■ नक्सली माओवाद गिनता अंतिम सांसें ..................................47
■ विकास बनाम विषमता ..................................................50
■ कुछ राजनेताओं का समर्थन आश्चर्यजनक... ? ..........................54
■ भोपाल गैस त्रासदी: समस्या से समाधान तक .............................58
■ 25 years of Jharkhand - who gained, who lost ? ................62

अपने सबसे अनुभवी प्लेयर को बैंच पर बैठाए रखोगे तो हम पर होंगे ही गोल पर गोल!
विजया :)

संपादकीय

# राष्ट्र चेतना, स्वाभिमान और सांस्कृतिक आत्मा का उद्घोष है वंदे मातरम

वंदे मातरम वह उद्घोष है जिसने गुलामी के अंधकार में जकड़े राष्ट्र को चेतना, साहस और संघर्ष का मार्ग दिखाया। वर्ष 1875 में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम आज अपनी 150वीं जयंती पर हमें स्मरण कराता है कि राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि साझा संस्कृति, त्याग और संकल्प से निर्मित जीवंत चेतना है। वंदे मातरम का जन्म उस दौर में हुआ, जब भारत औपनिवेशिक दासता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यह रचना बंकिमचंद्र की कालजयी कृति आनंदमठ का हिस्सा थी, लेकिन शीघ्र ही यह साहित्य की सीमाओं से बाहर निकलकर स्वतंत्रता आंदोलन का उद्घोष बन गई। जिस समय हथियार उठाना कठिन था, उस समय यह गीत ही सबसे सशक्त शस्त्र बना। स्वतंत्रता संग्राम के हर चरण में, चाहे वह कांग्रेस के अधिवेशन हों, क्रांतिकारियों की गुप्त सभाएं हों या जन आंदोलनों की अग्रिम पंक्तियाँ वंदे मातरम राष्ट्र की धड़कन बनकर गूंजता रहा।

वंदे मातरम की सबसे बड़ी विशेषता है मातृभूमि को देवी स्वरूप में देखने की दृष्टि। भारतीय परंपरा में भूमि केवल संसाधन नहीं, बल्कि जननी है। बंकिमचंद्र ने इसी दर्शन को शब्द दिए जहाँ खेत, नदियाँ, पर्वत और वन केवल प्राकृतिक तत्व नहीं, बल्कि राष्ट्र की जीवन रेखाएँ हैं। यह गीत हमें यह भी सिखाता है कि राष्ट्रभक्ति केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि कर्तव्यबोध से जुड़ी होनी चाहिए। मातृभूमि की वंदना तभी सार्थक है, जब उसकी रक्षा, उन्नति और सम्मान के लिए सतत प्रयास हों। 1905 के बंग-भंग आंदोलन से लेकर 1947 की आज़ादी तक, वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों का उर्जा स्रोत बना रहा। अंग्रेजी हुकूमत ने इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह गीत भारतीयों को भयमुक्त कर रहा है।

लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत क्रांतिकारियों के लिए वंदे मातरम् केवल नारा नहीं, बल्कि आत्मबल था। फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय भी अनेक वीरों के होंठों पर यही शब्द थे। स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। यह निर्णय भारत की बहुलतावादी आत्मा का प्रतीक है, जहाँ अलग-अलग भाषाएँ, धर्म और संस्कृतियाँ होते हुए भी राष्ट्र की भावना एक है। आज जब भारत विश्व मंच पर एक उभरती शक्तिके रूप में स्थापित हो रहा है, तब वंदे मातरम हमें यह स्मरण कराता है कि आर्थिक प्रगति के साथ सांस्कृतिक चेतना का संतुलन आवश्यक है। विकास तभी सार्थक है, जब वह राष्ट्र की आत्मा से जुड़ा हो। आज के समय में जब उपभोक्तावाद, व्यक्तिगत स्वार्थ और वैचारिक ध्रुवीकरण समाज को प्रभावित कर रहे हैं, वंदे मातरम् की भावना और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। यह गीत हमें जोड़ता है- भाषा से परे, मत से परे, वर्ग से परे। यह हमें यह प्रश्न भी देता है-क्या हम आज भी उतनी ही निष्ठा से अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभा रहे हैं? क्या स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और ईमानदारी भी राष्ट्रभक्तिके ही रूप नहीं हैं? आज की युवा पीढ़ी के लिए वंदे मातरम को केवल पाठ्यपुस्तक या औपचारिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसके पीछे छिपे संघर्ष, विचार और आत्मसम्मान को समझाना आवश्यक है। डिजिटल युग में राष्ट्रभक्तिका स्वरूप बदला है, लेकिन उसका मूल भाव आज भी वही है राष्ट्र सर्वोपरि।

**विजया पाठक**

बिहार चुनाव

# तिकड़ी की तिकड़म

## लोकतंत्र नहीं नमोतन्त्र है ये

बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। इस बार बिहार का यह चुनाव काफी दिलचस्प था। महागठबंधन और एनडीए में सीधे टक्कर देखी जा रही थी लेकिन एनडीए को भारी बहुमत मिला और महागठबंधन बहुत खराब स्थिति में आ गया। एनडीए को इतना ज्यादा बहुमत मिलेगा इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। राजनीतिक विश्लेषक भी इन परिणामों को संदेह की नजरों से देख रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बिहार में केवल 7.42 करोड़ हैं जबकि चुनाव आयोग के आकड़ों में इसे 7.45 करोड़ दर्शाया जा रहा है। आखिर ये तीन लाख मतदाता कौन हैं, जो आकड़ों में फिट नहीं बैठ रहे हैं। विपक्ष का तो यहां तक कहना है कि ये तीन लाख लोग आरएसएस और बीजेपी के हैं, जिन्होंने चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया। दूसरी तरफ एसआईआर के माध्यम से बिहार में करीब 69 लाख मतदाताओं के नाम काटे गये हैं। विपक्ष ने पूरे चुनाव में एसआईआर का विरोध किया। आखिर इसी समय एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी ? तीसरी और अहम बात ये हैं कि आखिर चुनाव के पहले राज्य की करीब 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रूपये की राशि दी गई। क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंखन नहीं है ? ये ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जिनका जबाव आज पूरा देश जानना चाहता है। सत्ता के सामने हमारी संवैधानिक संस्थाएं कटपुतली बन गई हैं जिन्हें जैसा चाहे वैसा नचाया जा सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और आबादी के हिसाब से भी सबसे बड़े हैं। यही कारण है कि भारत की हर एक उठापटक पर विश्व की नजरें होती हैं। वह चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक हों। पिछले एक दशक में तो हमारे लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल गई है। जिसकी सत्ता है उसका बोलबाला है, सरकारी मिशनरी भी उसकी है और संसाधन भी उसके ही हैं। निश्चित ही विश्व के अंदर अब लोकतंत्र के मामले में भारत की छबि धूमिल हो रही है।

क्या हमारा लोकतंत्र अब लोभ, नियमों के उल्लंघन और फर्जीवाड़ा की बैसाखियों पर आ खड़ा हो गया है ? पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र की ये कौनसी परिभाषा गढ़ी जा रही है। जिसमें साम, दाम, दंड और भेद का बहुतायत उपयोग होने लगा है। बिहार में 2025 का चुनाव राजनीतिक गठबंधनों या दलों के बीच का चुनाव नहीं था, बल्कि सत्ता पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्रकारी पटकथा थी। भारत में यह लोकतांत्रिक स्वरूप में उभरकर आया है, जिसने सत्ता पर कब्जा करने के तौर-तरीकों को भी बदल डाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने एक राजनीतिक शक्ति के रूप में निर्णय लेने की अपनी शक्ति खो दी है। लोकतंत्र की

कामयाबी के लिये ज़रूरी है कि सरकार अपने निहित स्वार्थों से उपर उठकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करे। विकास के तमाम दावों के बावजूद देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी आदि बेहद गंभीर समस्याएं है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी करोड़ों लोग दयनीय जीवन जीने को मजबूर हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतांत्रिक शासन-पद्धति के अंग होते हैं, लेकिन इन तीनों में ही अव्यवस्था का बोलबाला है और ये बेहद दबाव में काम करती हैं। जनता की भागीदारी की कमी की वज़ह से ही हमारा लोकतंत्र महज एक चुनावी लोकतंत्र बनकर रह गया है। चुनाव में मतदान का प्रयोग एक अधिकार के रूप में नहीं, एक कर्तव्य के रूप में किया जाने लगा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बुनियादी सवाल कहीं पीछे छूट गए हैं और लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और लोकतांत्रिक संस्कृति को विकसित करने के लिये पहले बुनियादी समस्याओं को हल किया जाना ज़रूरी है ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाया जा सके। सवाल उठने लगा है कि अब से भारत के नागरिक समय-समय पर उपयोग में लाए जाने वाले वस्तु बनकर रह जाएंगे? यह इस कारण कि भारत के हर एक चुनाव में वोट देने वाली जनता अब केवल एक अदृश्य, अपरिहार्य और बिखरे समूह में परिवर्तित हो गई है। जिसके पास शक्ति और संसाधन होते हैं वह चुनाव के परिणामों को बदलने की क्षमता रखता है।

बिहार चुनाव में पलायन, बेरोजगारी, गरीबी और उद्योग जैसे बुनियादी मुद्दे एक दम हाशिये पर चले गये। जब नतीजे आए तो राष्ट्रीय स्तर के सभी एग्जिट पोल के अनुमान वास्तव में गलत रहे, क्योंकि आंकड़े उनके अनुमान से भी काफी ज्यादा थे। लेकिन वह अनजान एग्जिट पोल ज्यादा करीब नजर आया। 243 में से 202 सीटें अंतिम आंकड़े थे। भाजपा ने 89, जदयू ने 85 और शेष सीटें उनके सहयोगी दलों को प्राप्त हुए। यह नतीजा सभी को चौंकाने वाले थे। चुनाव में महागठबंधन की लगभग संपूर्ण हार दिखी। महागठबंधन को मिले 35 सीटों में 25 राजद के पक्ष में गए। 2010 के बाद यह राजद की सबसे बड़ी हार है। तब राजद को 22 सीटें मिली थीं। क्या अधिकतर मतदाताओं ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया? विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 37.3 फीसदी तक कैसे गिर गई? 2024 के लोकसभा चुनावों से महागठबंधन को इस बार 2.8 फीसदी वोट कम मिले। वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। निश्चित ही बिहार के नतीजे सबको चौका रहे हैं। इसमें भले ही विपक्ष के आरोपों में सच्चाई न हो लेकिन कहीं न कहीं आकड़े संदेह जरूर पैदा कर रहे हैं।

विजया पाठक

बीते 20 वर्षों में नीतीश कुमार दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस बार के बिहार चुनाव को समझने के लिए राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक-आर्थिक जनसांख्यिकी का आंकलन करना होगा। बिहार के चुनाव के परिणाम का एक और निहितार्थ सामने आया है। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में, जहां गरीब, दलित, उत्पीडति और हाशिए के लोग सबसे बड़ा वर्ग है, वहीं इस चुनाव के दौरान सामाजिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जाति संगठनों के नेताओं ने राजनीतिक निर्णय और उससे जुड़े आयामों पर अपना दबदबा कायम रखा। देखा जाए तो कुछ शक्तिशाली जातियों के पास ही निर्णय लेने के सारे अधिकार रहे। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की प्रचंड जीत कभी किसी मुकाबले जैसी नहीं लगी। नतीजों के बाद कई विशेषज्ञों ने चिंता जताई कि क्या यह वाकई भारत के लोकतांत्रिक परिवेश का चुनाव था? अब समय आ गया है कि भविष्य के तस्वीर को समझ लिया जाए। अब से शायद ही चुनाव लड़ा जाएगा। पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से मतदाताओं को ट्रैप करने की योजनाएं बनाई जाएंगी। इस बार का बिहार चुनाव इसका प्रमाण है। एक ऐसा राज्य जहां पूरी आबादी जातिवाद में उलझी है, महिलाएं गुलामी झेल रही हैं, लगभग आधे युवा बेरोज़गारी की गिरफ्त में हैं, दलितों पर आज भी दिनदहाड़ अत्याचार व उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, अति पिछड़े वर्गो के सामाजिक मूल्य पर अभी भी बहस जारी है, बाढ़ की दोगुनी मार है और जहां लोग जिंदा रहने के लिए अंतर-राज्य प्रवासी मज़दूर बनकर देश के अलग-अलग प्रांतों में जाने को मजबूर हैं। राज्य के अधिकतर लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं

> **चुनाव के दौरान सामाजिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जाति संगठनों के नेताओं ने राजनीतिक निर्णय और उससे जुड़े आयामों पर अपना दबदबा कायम रखा**

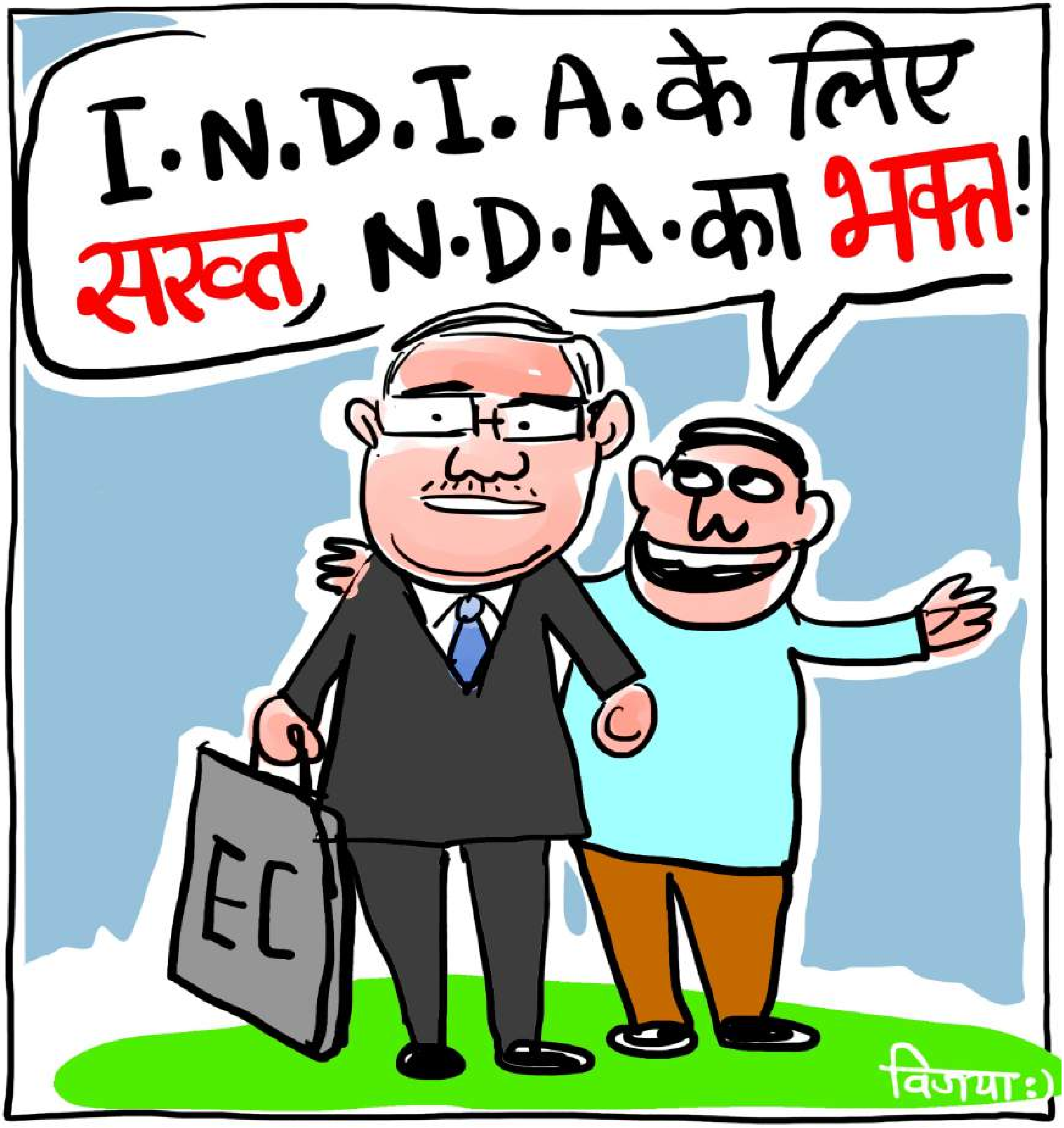


और राज्य के रोजगार के अवसर न के बराबर हैं लेकिन इसे विडंबना ही कहा जायेगा कि आज के परिदृष्य में ये मुददे गायब हैं। लोक लुभावन और चुनावी हथकंडे अपनाकर चुनाव में जीत प्राथमिकता हो गई है।

**लोकतंत्र और तानाशाही**

80 प्रतिशत से ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए ने बिहार में पुनः अपना परचम लहरा दिया और नीतीश 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। देश और विदेश में जो भी लोग भारत में सतह पर राजनीति, लोकतंत्र

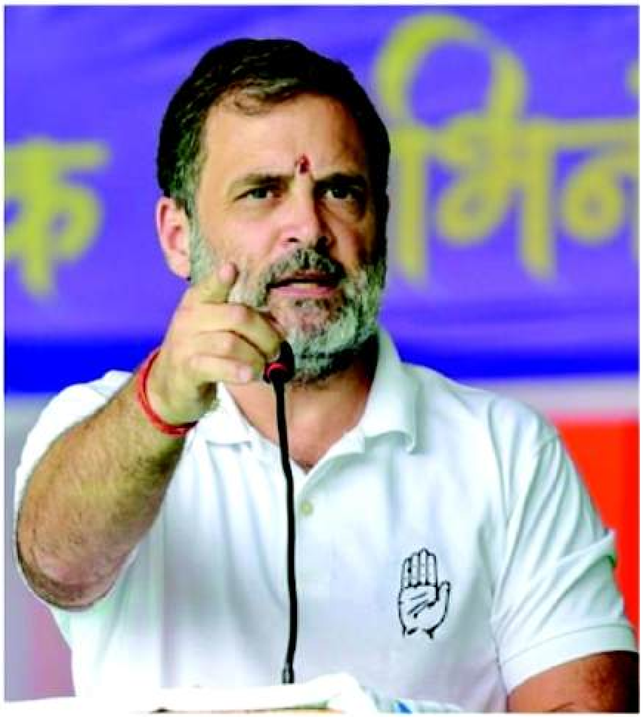

और समाज में चल रही अंत:क्रियाओं पर पैनी नजर रखे हुए थे। उन सभी की आश्चर्य मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। महाराष्ट्र, प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणामों ने पहले से ही महागठबंधन और विश्लेषकों को हैरत में डाल रखा था। राहुल गांधी के द्वारा चुनाव में हेरा-फेरी और धांधली के तार्किक भंडाफोड़ के बाद चुनावी भ्रष्टाचार और वोट चोरी का

# क्या लोकतंत्र पर धनबल-बाहुबल हो गया है हावी?

हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एकतरफा जीत के बाद मोदी-शाह और नीतीश की तिकड़ी बिहार जीत पाएगी या नहीं। इस विषय पर अलग-अलग विचार थे। जमीनी हालात को देखते हुए प्रेक्षकों की राय थी कि इंडिया और एनडीए के मध्य तीखे संघर्ष होंगे। 05 वर्ष पहले हुए चुनाव के परिणाम विवादास्पद थे। उस समय एनडीए ने 10 सीटों की बढ़त मतगणना में धांधली से बनाई थी। ऐसा आम जन मानस की धारणा है। ऐसा लग रहा था कि लोग जनादेश के अपहरण का हिसाब करने के लिए 05 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। मध्य

**देश और विदेश में जो भी लोग भारत में सतह पर राजनीति, लोकतंत्र और समाज में चल रही अंत:क्रियाओं पर पैनी नजर रखे हुए थे। उन सभी की आश्चर्य मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है**

सवाल राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। एसआईआर में 70 लाख वोट काटे जाने के बाद बिहार में वोट चोरी का नारा गली-गली गूंजने लगा। वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा आम बातचीत और प्रचलन में आ गया। जिससे 70 के दशक के बिहार की याद ताजा हो रही थी। इस चुनाव में दोनों गठबंधनों के मुद्दे स्पष्टत: अलग-अलग विचारों और सामाजिक सरोकारों को अभिव्यक्त कर रहे थे। एनडीए घुसपैठिये और बांग्लादेशियों को बाहर निकालने तथा लालू राज के गढ़े गये नरेटिव जंगलराज को मुख्य मुद्दा बनाए हुए था। ऑपरेशन सिंदूर सेना का पराक्रम और

विकास जैसे मुद्दे भी बीच-बीच में उठ जा रहे थे। हिंदुत्व का तड़का मिलाए बिना तो भाजपा चुनाव लड़ ही नहीं सकती। पाकिस्तान, इस्लाम और आंतरिक दुश्मन का मुद्दा भाजपा के लिए संजीवनी है तो उसे वह छोड़ नहीं सकती। महागठबंधन की कोशिश थी कि बिहार चुनाव को जनता के मुद्दे के इर्द-गिर्द केन्द्रित रखा जाए तथा अन्य राज्यों में हुए चुनावों में धांधली को लोकतंत्र के लिए खतरे तथा बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के दमन उत्पीड़न के साथ संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के सवाल को चुनावी एजेंडा बनाया जाए। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों जीविका दीदी शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी आदि के सवाल को इंडिया गठबंधन के एजेंडे में प्रमुख जगह मिली थी।

किसानों की कर्ज माफी, गरीब मजदूर महिलाओं के उपर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज जाल से मुक्ति को मुद्दा बनाया गया। महागठबंधन ने संकल्प पत्र जारी कर विभिन्न तबकों और वर्गों के सवालों को ठोस करने की कोशिश की। अति पिछड़ों के लिए विशेष पैकेज और अधिकार की मांग की गई। महागठबंधन ने एनडीए के विभाजन कारी अभियान के खिलाफ वास्तविक जन

# एक बार फिर कटघरे में चुनाव आयोग

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का सारा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही है। भारत में करीब 97 करोड़ योग्य मतदाता हैं। लेकिन चुनाव का दौर ऐसा है जब चुनाव आयोग आरोपों और विवादों के केंद्र में होता है। बिहार में चुनाव आयोग पर कई दूसरे आरोप भी लग रहे हैं। बिहार चुनाव में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव घोषित होने के तुरंत पहले 10,000 रूपये बांटने का ऐलान हुआ और आचार संहिता के दौरान हर हफ्ते महिलाओं को पैसा ट्रांसफर हो रहा था और चुनाव आयोग दिल्ली में बैठा तमाशा देख रहा था। बिहार में एनडीए ने नहीं, बल्कि चुनाव आयोग ने इलेक्शन जीता है। कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने एनडीए को बिहार में चुनाव को ख़रीदने दिया। चुनाव आयोग ने 10,000 रुपए देकर वोट ख़रीदने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। साफ दिखा कि बिहार में चुनाव आयोग एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा था।

विपक्ष सरकारी एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग का आरोप पहले से लगाता आया है। विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ बीजेपी को लेकर बेहद नर्म है और विपक्ष को लेकर गर्म। कांग्रेस और महागठबंधन ने वोटर लिस्ट, अधिकारियों की नियुक्ति और निष्पक्ष मतदान पर गंभीर सवाल खड़े किए। आरोप है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटा दिए गए या मनमाने ढंग से जोड़े-घटाए गए। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव आयोग की भूमिका और उस पर उठते सवालों ने एक बार मुद्दों और बिहार के पिछड़ेपन के सवाल के इर्द-गिर्द चुनाव को केंद्रित रखने की कोशिश की।

बिहार चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका ने इस बात का संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है। नौकरशाही न्यायपालिका और स्वायत्त संस्थाएं सरकार के समक्ष घुटने

**एनडीए की ऐतिहासिक जीत और महागठबंधन की करारी हार के बीच, मुख्य सवाल यही उठा कि क्या चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन किया? साथ ही, आचार संहिता के उल्लंघन, राजनीतिक दलों के आचरण और आयोग पर दोहरे मानदंडों के आरोपों ने भी चुनावी निष्पक्षता की मूल भावना को चुनौती दी है।**

फिर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर बहस छेड़ दी है। एनडीए की ऐतिहासिक जीत और महागठबंधन की करारी हार के बीच, मुख्य सवाल यही उठा कि क्या चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन किया? साथ ही, आचार संहिता के उल्लंघन, राजनीतिक दलों के आचरण और आयोग पर दोहरे मानदंडों के आरोपों ने भी चुनावी निष्पक्षता की मूल भावना को चुनौती दी है। विपक्ष ने मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि आयोग की प्रक्रिया आमजनता का भरोसा कायम नहीं रख पा रही है। चुनाव में लगभग सभी प्रमुख दलों के सोशल मीडिया पर भड़काउ, जातिवादी और भ्रामक कंटेंट साझा होने के आरोप लगे। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ऐसी लगभग 21 एफआईआर दर्ज की, जिनमें भाजपा, राजद और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग की सबसे अहम जिम्मेदारी है, चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना। आयोग को अपने हर कदम पर समानता और पारदर्शिता का पालन करना चाहिए। आयोग की साख को बहाल करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। बिहार चुनाव में चुनाव आयोग की निष्पक्षता, राजनीतिक दलों का आचरण और विजेता की रणनीति सभी गंभीर चर्चा का विषय रहे। आयोग को चाहिए कि वह अपने हर निर्णय में पारदर्शिता, कठोरता और समान व्यवहार बनाए रखे, तभी वह जनता का भरोसा लौटाने में कामयाब होगा। साथ ही विपक्ष को चुनावी रणनीति बनाने और आंतरिक समन्वय में अपनी कमियों से सीख लेनी होगी, ताकि वे सशक्त विकल्प बन सकें और लोकतंत्र को मजबूती दे सकें। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के मुद्दे पर बढ़ते विवाद को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। एक ऐसा चुनाव आयोग, जिसका बचाव इन दिनों केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो अन्यथा बदनाम है, एक गहरी क्षति है जिसे भाजपा या उसके सहयोगियों के विजय उत्सवों से नहीं धोया जा सकता।

भारत में एक समय था जब चुनाव परिणाम चाहे जो भी हों, भारतीय चुनाव आयोग को भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं का मुख्य रक्षक माना जाता था। ईसीआई शुरूआत में शांत था, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के कार्यकाल में एक शेर बन गया और तब से इसने एक प्रखर रक्षक और भारत की लोकतांत्रिक सफलता के लिए आवश्यक तत्व-चुनाव प्रक्रिया के स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में अपनी छवि को बनाए रखा है। चुनाव का समय आते ही राजनीतिक दल अपनी सीमाओं की परीक्षा लेते हैं, लेकिन ईसीआई डटकर खड़ा होता था। वह यह सुनिश्चित करता कि उल्लंघनों की पहचान हो और वास्तव में जांच और निगरानी को बढ़ाता था ताकि प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष हो बल्कि ऐसी दिखाई भी दे। अब उस स्वर्णिम युग को भारतीय चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा न रह जाने के रूप में देखे जाने की संभावना है। आज चुनावों की समाप्ति के साथ ही परिणामों को लेकर एक नई लड़ाई शुरू हो गई है, एक ऐसी गिरावट जो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था और एक युवा राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास के लिए गंभीर चिंता का विषय होनी चाहिए, जिसने स्वतंत्रता के बाद से सफलतापूर्वक एक उचित और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संचालित की है।

टेक चुकी है। कानून का शासन अंतिम सांसें गिन रहा है। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को तिलांजलि देकर भारतीय राज्य खुलकर बहुसंख्यकवादी हो गया है। नागरिक समाज कमजोर हो चुका है। उस पर हमले जारी हैं। भीड़ न्याय का सिद्धांत थोपा जा रहा है। मीडिया पर सरकार का कब्जा है। विपक्ष को खलनायक और विरोधियों को देशद्रोही पाकिस्तान परस्त कहकर गालियां दी जा रही

# मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर संकट पैदा करेगी एसआईआर की योजनाबद्ध साजिश

राज्य में मतदाता सूची का निर्माण केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की पूरी बुनियाद है। चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और विश्वसनीयता इसी पर निर्भर करती है। ऐसे में जब निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार द्वारा मतदाता सूची की जांच, अर्थात एसआईआर (स्पेशल समरी रिविजन) प्रक्रिया को जल्दबाज़ी और आधी-अधूरी तैयारी के साथ लागू किया गया है तो यह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे के साथ खिलवाड़ भी प्रतीत होता है। यह कहना पूरी तरह सार्थक है कि एसआईआर प्रक्रिया जिस तरह शुरू की गई है, उसने मतदाता सूची निर्माण की पूरी प्रक्रिया का मज़ाक बना दिया है। जिस कार्य के लिए महीनों की तैयारी, सुचारू समन्वय और पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसे केवल दिखावे की तत्परता में शुरू कर दिया गया है, जिसके परिणाम गंभीर रूप से मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि हर नागरिक को मताधिकार का अवसर मिले और उसे सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का दायित्व है। आयोग केवल काग़ज़ों पर नियम लिखकर मुक्त नहीं हो सकता। वास्तविक अमल ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए और उसी से आयोग की विश्वसनीयता बनती है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आयोग अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाए, राज्य सरकार सभी संसाधन समय पर उपलब्ध कराए और मतदाता सूची की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से दोबारा प्रारंभ किया जाए।

एसआईआर चुनावी राजनीति का अनूठा प्रयोग है। एसआईआर की योजना जून महीने में अचानक बिहार पर थोप दी गई। जिसके लिए सिर्फ एक महीने का समय दिया गया। नागरिकों और राजनीतिक दलों के लिए यह घोषणा आश्चर्य चकित करने वाली थी। ऐसा लगता है कि मोदी-शाह की जोड़ी इसी के साथ मिलकर इस पर लंबे समय से काम कर रही थी। एसआईआर का समय तरीका जरूरी दस्तावेज तथा लागू कराने वाली मशीनरी सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार की गई थी। इसलिए अनेकों

हैं। अल्पसंख्यकों स्त्रियों, दलितों आदिवासियों पर हिंदुत्व वादियों और पुलिस प्रशासन का हमला बढ़ रहा हैं। मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और राज्य के बुलडोजरी न्याय को सामाजिक स्वीकृति मिल रही है। ऐसी स्थिति में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे कानून के राज और सामाजिक एकता को बचाना बिहार में चुनाव का मुख्य परिप्रेक्ष्य था।

विसंगतियों, कमियों, जटिलताओं के बावजूद चुनाव आयुक्त पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। पूर्व चुनाव आयुक्तों से लेकर विपक्ष और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने एसआईआर की कष्ट साध्य जटिल अव्यवहारिक और संविधान विरोधी अंतर्वस्तु पर सवाल उठाए। न्यायालय के बार-बार सुझाव देने के बावजूद चुनाव आयुक्त प्रस्तुत किए जाने वाले 12 दस्तावेजों में संशोधन परिवर्धन के लिए तैयार नहीं थे। अभी तक पहचान तय करने वाले मान्य डॉक्यूमेंट जैसे निर्वाचन कार्ड आधार कार्ड राशन कार्ड पासपोर्ट बैंक पास बुक पैनकार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों को एसआईआर के लिए अमान्य करार दिया गया। अंत में जब न्यायालय ने आधार कार्ड को शामिल करने का आदेश दिया तब जाकर इसे बेमन से मान्यता दी गई।

इस सम्पूर्ण घटनाक्रम से स्पष्ट है कि सरकार और चुनाव आयोग का एसआईआर के पीछे छिपा और सुचिंतित एजेंडा था। जो एसआईआर पूरा होने के बाद सामने आया। जब 67 लाख मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए। इसके बाद हुए प्रतिवाद और विभिन्न तरह के कानूनी तथा राजनीतिक दबाव के बावजूद चुनाव आयोग विसंगतियों को दूर करने का दिखावा करता रहा। इसकी आड़ में भी उसने कई खतरनाक खेल-खेले। यही नहीं बार-बार सूची सार्वजनिक करने की मांग के बावजूद चुनाव आयोग तरह-तरह की हीला हवाली करता रहा और अंत तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। जिस कारण से वास्तविक मतदाता जब मतदान पहचान पत्रों के साथ पोलिंग बूथों पर गए तो पता चला की सूची से उनका नाम गायब है। इस संदर्भ में जांच पड़ताल करने वाली संस्थाओं का कहना है कि एसआईआर की कवायद के शिकार अल्पसंख्यकों दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और कमजोर वर्गों को होना पड़ा है। चुनाव परिणाम आने के बाद डरा देने वाली खबरें आ रही हैं। कथित तौर पर 100 के आसपास ऐसी विधान सभाएं हैं जहां एनडीए के प्रत्याशियों की विजय उतने ही मतों से हुई है जितने मतदाता लोकसभा के चुनाव में मतदान करने के बावजूद सूची से बाहर किए गए थे। मतगणना के बाद चुनाव परिणाम में कई ऐसे संयोग देखे गए हैं जो चिंतित कर देने वाले हैं। कई मंत्रियों को एक जैसे वोट मिले हैं जिसमें शुरू के तीन डिजिट एक ही थे। जैसे 01 लाख 224 के बाद के ही अंकों में फ र्क दिखाई देता है। आपको याद होगा कि हरियाणा में एक ही विधानसभा में कुछ बूथों पर एक ब्राज़ीलियन हेयर ड्रेसर का फोटो 22 जगह चस्पा मिला था। देश जानता है कि यह मोदी काल है। जहां सब कुछ मुमकिन है।

बिहार मोदी और शाह के नये भारत की परियोजना का प्रयोग स्थल था। जहां वह हिंदुत्व कॉरपोरेट चुनावी मॉडल का परीक्षण करने में सफल रहे। अब भारत दुनिया की उन 73 प्रतिशत आबादी वाले देशों में शामिल हो गया है। जहां चुनावी तानाशाही अबाध गति से चल रही है। बाकी सब भविष्य में दिखाई देगा। भारत का लोकतंत्र कई अलग-अलग दिशाओं में जा रहा है,

जिसमें एक ओर जहाँ वैश्विक पटल पर इसकी लोकतांत्रिक साख पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार और उसके समर्थक इसे एक मजबूत और उभरते हुए मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। विभिन्न अध्ययनों और सूचकांकों ने नागरिकों की भागीदारी, विश्वसनीय चुनावों और न्यायपालिका की पहुँच जैसे क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की है, जो चिंता का विषय है। इसके

# लोकतंत्र में मतदाता का क्या महत्व है?

इस चुनाव ने निश्चित रूप से इस सवाल को फिर से केंद्र में ला दिया है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाताओं का क्या महत्व है? बिहार चुनाव ने साबित कर दिया कि वोटर और उसके वोट का कोई महत्व नहीं है। जो सत्ता पर काबिज हुआ, उसी का वजूद है, बाकी सब गौण हैं। इस चुनाव से सबसे बड़ी सीख यह है कि मतदाताओं को या तो पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है या पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सकता है। दरअसल बिहार मतदान के नतीजे, बुनियादी तौर से चुनाव प्रचार के दौरान जमीन पर छाए माहौल को नहीं दर्शाते। बात बिल्कुल साफ है कि जमीनी माहौल और नतीजों में बहुत बड़ी गहरी खाई है। ऐसा लगता है कि भारत का चुनावी लोकतंत्र उस खाई में दबकर मरती जा रही है।

विपरीत, सरकार और उसके समर्थक यह दावा करते हैं कि भारत आत्मविश्वास और विकास की ओर बढ़ रहा है और एक उभरता हुआ मॉडल बन रहा है। भारत वैश्विक लोकतांत्रिक मंदी का उदाहरण है। भारत के लोकतांत्रिक पतन का तरीका

कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और कई अन्य नेता पिछले कुछ समय से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ के पहले के दावों के अलावा, राजनीतिक हलकों को अब पता चला है कि वोटों में हेराफेरी कई तरीकों से हो सकती है। चुनाव आयोग और राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने इन आरोपों का त्वरित खंडन किया। बिहार के इस बार के चुनाव में एक दिलचस्प बात यह है कि एक एग्जिट पोल ऐसा भी था, जिसने एनडीए का 243 सीटों पर जीत की भविष्यवाणी की थी। यह इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि अधिकांश एग्जिट पोल ने एनडीए के पक्ष में 130 से 170 सीटों के बीच भविष्यवाणी की थी। ऐसा पहली दफा हुआ कि किसी एग्जिट पोल ने किसी एक पार्टी या गठबंधन के पक्ष में सभी सीटें जीतने की बात कही। बिहार के चुनाव में जीत में मतदाताओं द्वारा डाले गए वोटों से कहीं ज्यादा धांधली की भूमिका रही।

भारत में जातिवाद और पूंजीवाद एक-दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। इनका प्रभाव अब सीधे तौर पर चुनाव प्रणाली पर दिखता है। काफी अरसे से जातिवाद पर गहन चर्चा होती रही। बिहार में 2025 का चुनाव राजनीतिक गठबंधनों या दलों के बीच का चुनाव नहीं था, बल्कि सत्ता

दर्शाता है कि आज लोकतंत्र कैसे दम तोड़ रहे हैं। सरकार की आलोचना को राष्ट्र के प्रति बेवफ़ाई के बराबर मानकर, नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष के वैध होने के विचार को ही कमज़ोर कर रही है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं रहा। वैश्विक

पर कब्जा करने के लिए दिल्ली में लिखी गई पटकथा थी। भारत में यह लोकतांत्रिक स्वरूप में उभरकर आया है, जिसने सत्ता पर कब्जा करने के तौर-तरीकों को भी बदल डाला है। इसके कुछ परीक्षण और प्रयोग बहुत पहले ही शुरू हो गए थे। खासकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान और बाद में हरियाणा और अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार हुआ। अब यह बिहार में बड़े पैमाने पर प्रवेश कर चुका है। पहली चाल रही, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) अथवा विशेष गहन पुनरीक्षण। चुनाव आयोग ने एसआईआर को शुद्धिकरण के कारणों के बहाने लागू किया। लेकिन लोकतंत्र की नसों पर एक सुनियोजित सर्जिकल स्ट्राइक रहा। वैसे यह सर्जिकल स्ट्राइक अभी भी जारी है। मतदाता सूची की सावधानी से जांच की गई। नई सूची से कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चाहे वे गांव के हों या फिर शहर के।

मतदाताओं के नाम बहीखाते से हटाई गई प्रविष्टियों की तरह, वे गायब हो गए। इस बात को अब हमें समझना होगा कि जब मतदाता सूची का आकार छोटा कर देता है, तो वहीं पर लोकतंत्र मर जाता है। दूसरी चाल रही पैसे की बारिश। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए। यह भाजपा सहित अपने सहयोगी दलों की ओर से विभिन्न राज्यों में अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त हासिल करने के लिए अपनाई गई एक सफल रणनीति का हिस्सा है। यह कोई कल्याणकारी योजना नहीं थी। यह एक रिश्वत थी। महिला मतदाताओं को लुभाने में भाजपा पहले से ही माहिर है। ऐसी ही चालें मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की लाडली बहना

लोकतांत्रिक मंदी का भारत से बेहतर उदाहरण कोई और देश नहीं दे सकता। अपनी स्थापना के समय की सबसे अप्रत्याशित बात यह थी कि भारत के लोकतंत्र ने अपने पहले सात दशकों में और अधिक स्थिर होकर आलोचकों को चकित

योजना और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना-एनसीपी की लाडकी बहीण योजना है। इन योजनाओं ने दोनों राज्यों में क्रमशः 2023 और 2024 में सत्ताधारी दल के लिए एक और कार्यकाल सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई थी। दोनों राज्यों में ये योजनाएं उसी साल शुरू की गई, जब वहां विधानसभा चुनाव होने वाला थे। यदि विपक्ष ऐसा कुछ डिजिटल माध्यम से करता या करवाता, तो वे निश्चित ही प्रवर्तन निदेशालय के छापे झेलते। यानि डिजिटल माध्यम से रिश्वत सरकारी रीति से सत्ता पर काबिज होने का एक आसान हथियार बन गया, जो कि अब सामान्य हो रहा है। अब जनता जनतंत्र में केवल लाभार्थी रह गई है। तीसरी चाल, यह कि लाल किला विस्फोट, जिसकी समयबद्धता अद्‌भुत थी और जिसका कोई वास्तविक समाधान भी नहीं था। इस घटना ने भय की पूरी संरचना तैयार कर दी। भय का प्रयोग मतदान के दौरान मतदाता का पक्ष और व्यवहार को प्रभावित करने का एक सटीक तरीका है। डर इंसान के राय को बदल सकता है। इससे कहीं मतदान बढ़ता है जहां सत्तासीन दलों को फायदा है। और यदि कहीं नुकसान की संभावना है तो मतदान को कम करवा देता है।

कई अध्ययनों के मुताबिक कई देशों में चुनाव प्रचार में राजनीतिक विरोधियों से वोट छीनने के लिए डर का इस्तेमाल किया जाता है। इस रणनीति के कई तरीके और आयाम होते है। कहीं यह एक घटना से राष्ट्रवाद का स्वरूप लेता है तो कहीं यह व्यक्तियों और नेताओं के बारे मे डर पैदा करना होता है। इसमें विरोधी उम्मीदवार की सीमाओं के बारे में झूठे या भ्रामक सूचना शामिल हैं। या यह भ्रामक दावा किया जाता है

कर दिया।

भारत ने दो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक पतन भी देखे हैं: जून 1975 से मार्च 1977 तक का 21 महीने का कालखंड जिसे आपातकाल के नाम से जाना जाता है और 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनाव से शुरूहुआ

कि विपक्ष की चुनावी जीत पूरी तरह से विनाशकारी होगी। व्यक्तिगत स्तर पर जब कोई राजनेता किसी प्रतिद्वंद्वी की शारीरिक या मानसिक अवस्था पर संदेह जताता है, तो अक्सर उसका लक्ष्य डर का इस्तेमाल करके समर्थकों को नेताओं और उम्मीदवारों की योग्यता पर संदेह उत्पन्न करना होता है।

इस तरह की योजना में मीडिया की भूमिका सत्तासीन दल के चीयरलीडर या प्रति ध्वनि के रूप में रहती है। वास्तव में मीडिया द्वारा बिहार एग्जिट पोल ने नतीजों का पूर्वानुमान नहीं लगाया था, क्योंकि इसकी पटकथा बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। मीडिया अब केवल उसकी पुष्टि करने का काम करती है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ी। यह एक नई ताकत लग रही थी, पर कुछ नहीं कर पाये। उसने जाति और वंशवाद की राजनीति से मुक्त युवाओं द्वारा संचालित एक मंच बनाने में तीन साल लगाए थे। पूरे चुनाव में इसका वोट शेयर 2.8 फीसदी रहा। इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव से महागठबंधन को 2.8 फीसदी वोट का नुकसान हुआ। ऐसे में विधानसभा चुनाव में विपक्ष का वोट केवल 37.3 फीसदी रह गया। जन सुराज पार्टी ने राजद के गढ़ों में सेंध लगाकर महागठबंधन को पूरी तरह से धूल चटा दी। इसने एनडीए के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उनके लिए चुनाव को एकदम से सुगम बना दिया। बहुत से सीटों पर हार-जीत का फासला 10 हजार वोटों से कम रहा।

एक समकालीन पतन। मोदी के कार्यकाल के दौरान, प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाएँ औपचारिक रूप से बनी रहीं, जबकि लोकतंत्र को आधार प्रदान करने वाले मानदंड और प्रथाएँ काफ़ी हद तक बिगड़ गई हैं।

फिर भी लोकतंत्र के प्रहरी इस बात पर सहमत हैं कि आज भारत पूर्ण लोकतंत्र और पूर्ण निरंकुशता के बीच कहीं निचले स्तर पर है।

भारत के लोकतांत्रिक पतन का मूल्यांकन करने के लिए, सबसे पहले लोकतंत्र को परिभाषित करना आवश्यक है, क्योंकि भारत के लोकतांत्रिक पतन पर बहस का निर्णय वैचारिक स्पष्टता पर निर्भर करता है और इसलिए भी कि लोकतंत्र निःसंदेह मानक वैधता का प्रतीक है। लोकतंत्र एक ऐसी अवधारणा है जो अब्राहम लिंकन के शब्दों में, जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली का प्रतीक है। लोकतंत्र के गैर-मानक आयामों पर स्पष्टता, जो इस विचार को क्रियान्वित करते हैं, हमें उन मानदंडों की ओर इंगित करती है जिनका उपयोग हम भारत के लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करने के लिए कर सकते हैं।

लोकतंत्र के लिए दो और संस्थाएँ भी वैचारिक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे नागरिकों और सरकार की स्वतंत्र शाखाओं, दोनों को सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती हैं। नागरिक स्वतंत्रताएँ (विधिपूर्वक और वास्तविक रूप से) चौथा स्तंभ और कार्यपालिका नियंत्रण, पाँचवाँ स्तंभ। कई प्रमुख विद्वानों ने सही तर्क दिया है कि लोकतंत्र की वे परिभाषाएँ जिनमें बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताएँ शामिल नहीं हैं, अपर्याप्त हैं। 4 एक स्वतंत्र प्रेस जो आलोचनात्मक जनमत के निर्माण को सक्षम बनाता है, उसे नागरिक स्वतंत्रता के इस स्तंभ का हिस्सा समझा जा रहा है। लोकतंत्र का अंतिम संस्थागत स्तंभ, कार्यपालिका नियंत्रण, एक निर्वाचित सरकार प्रमुख को यह घोषित करने से रोकता है कि 'मैं यही चाहता हूँ'। लोकतंत्र संस्थाओं का एक समूह है जो सरकारी जवाबदेही की प्रथा को अंतर्निहित करता है। यह जवाबदेही दो रूप लेती है: जनता और निर्वाचित सरकार के उच्चतम स्तरों, आमतौर पर चुनावों और वैकल्पिक राजनीतिक ताकतों के बीच

> **भारत के लोकतांत्रिक पतन का मूल्यांकन करने के लिए, सबसे पहले लोकतंत्र को परिभाषित करना आवश्यक है, क्योंकि भारत के लोकतांत्रिक पतन पर बहस का निर्णय वैचारिक स्पष्टता पर निर्भर करता है और इसलिए भी कि लोकतंत्र निःसंदेह मानक वैधता का प्रतीक है**

# बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने गढ़ी लोकतंत्र की नई परिभाषा

जवाबदेही; और कार्यपालिका और स्वतंत्र संस्थाओं, आमतौर पर स्वतंत्र विधायिकाओं और न्यायालयों के बीच क्षैतिज जवाबदेही, जो एक निर्वाचित कार्यपालिका को नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचलने से रोक सकती हैं।

**क्या भारतीय लोकतंत्र को बचाया जा सकता है?**

दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह, भारत में भी लोकतंत्र आज किसी सैन्य तख्तापलट या विरोधियों की नाटकीय, सुनियोजित सामूहिक गिरफ्तारियों के कारण दम नहीं तोड़ रहा है। इसके बजाय, तानाशाहों ने लोकतांत्रिक ढंग से बात करना और तानाशाही ढंग से चलना सीख लिया है,

लोकतंत्र का क़ानूनी मुखौटा बनाए रखते हुए विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। भारत में लोकतांत्रिक पतन वास्तविक है, लेकिन इसे पलटा नहीं जा सकता।

**क्या है वर्तमान स्थिति?**

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की लगभग 36 करोड़ आबादी अभी भी स्वास्थ्य, पोषण, स्कूली शिक्षा और स्वच्छता से वंचित है। दूसरी तरफ देश का

> **दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह, भारत में भी लोकतंत्र आज किसी सैन्य तख्तापलट या विरोधियों की नाटकीय, सुनियोजित सामूहिक गिरफ्तारियों के कारण दम नहीं तोड़ रहा है। इसके बजाय, तानाशाहों ने लोकतांत्रिक ढंग से बात करना और तानाशाही ढंग से चलना सीख लिया है, लोकतंत्र का क़ानूनी मुखौटा बनाए रखते हुए विपक्ष को परेशान कर रहे हैं।**

**भारत के इस 1 फीसदी समूह ने देश के 73 फीसदी धन पर कब्ज़ा किया हुआ है। लैंगिक भेदभाव भी बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 108वें पायदान पर है**

बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 108वें पायदान पर है और UNDP द्वारा जारी लिंग असमानता सूचकांक-2017 में भारत को 127वें स्थान पर रखा गया है। लोकतंत्र का चौथा खंभा माने जाने वाले मीडिया की आज़ादी भी सवालों के घेरे में है। दरअसल, पेरिस स्थित गैर-सरकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स- 2018

बनती है।

**बिहार में चुनाव के दौरान 3 लाख वोटर बढ़ने पर कांग्रेस ने उठाए ये सवाल**

बिहार विधानसभा चुनाव ख़त्म होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बिहार में चुनाव के बीच तीन लाख वोटर जोड़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि जहां चुनाव शुरू होने से पहले 6 अक्टूबर को बिहार में वोटरों की संख्या क़रीब 7.42 करोड़ थी, वहीं ये आंकड़ा चुनाव के बीच

एक तबका ऐसा है जिसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय आय का 22 फीसदी हिस्से पर सिर्फ 1 फीसदी लोगों का कब्ज़ा है और यह असमानता लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह Oxfam के मुताबिक, भारत के इस 1 फीसदी समूह ने देश के 73 फीसदी धन पर कब्ज़ा किया हुआ है। लैंगिक भेदभाव भी

में भारत पहले की तुलना में दो स्थान नीचे उतरा है और इसे 138वाँ स्थान मिला। इन 71 वर्षों में अन्य बातों के अलावा सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और कट्टरवाद को भी प्रश्रय मिला। इसकी वज़ह से असहिष्णुता की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। जातिवाद की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं। निःस्संदेह इस तरह की परिस्थितियाँ लोकतंत्र की कामयाबी की राह में बाधक

**विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय आय का 22 फीसदी हिस्से पर सिर्फ 1 फीसदी लोगों का कब्ज़ा है और यह असमानता लगातार तेज़ी से बढ़ रही है।**

मध्यप्रदेश काँग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई नेताओं को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उनकी अनुभवहीन कार्यशैली ने पार्टी की लंका डुबा दी। वहीं कमलनाथ जैसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता को इस चुनाव से दूर रखना सोचनीय है। कमलनाथ जैसे नेताओं की आज पार्टी को बहुत जरूरत है।

11 नवंबर को 7.45 करोड़ हो गया। आंकड़ों के इस फर्क को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग से सवाल कर रही है। बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर कर 69 लाख वोट काट दिए, जिनके वोट काटे गए, वे विपक्ष के वोटर थे, जिन्हें टारगेट कर लिस्ट से बाहर किया गया।

**चुनावी वादे और हमारा लोकतंत्र**

बहरहाल चुनाव चाहे किसी राज्य की सरकार का हो या केंद्र की सरकार का, हर राजनैतिक दल मतदाताओं को लुभाने की मंशा से ऐसे कई वादे करते हैं जो वास्तव में सच नहीं किए जाते। यदि जनता को चुनावों में किए गए वादों और उन्हें पूरा किए जाने के अंतर की देखा जाए तो यह अंतर काफ़ी बड़ी संख्या में पाया जाएगा। चुनावों से पहले ऐसे वादे हर राजनैतिक दल द्वारा किए जाते हैं। जिस तरह बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार में अपना विश्वास जताया है उससे यह बात तो तय है कि जनता को किए गए चुनावी वादे काफ़ी लुभावने थे। परंतु मतदाताओं यह सोचना होगा कि वादों की सूची और उन्हें पूरा करने में जिस भी दल का अंतर सबसे कम हो वही दल जनता के हित की सोचता है, तभी उसी दल को चुना जाता है। यदि सभी दल एक समान हैं तो जनता को चुनावी वादों से भ्रमित होकर इनमें फंसना नहीं चाहिए।

> **चुनाव चाहे किसी राज्य की सरकार का हो या केंद्र की सरकार का, हर राजनैतिक दल मतदाताओं को लुभाने की मंशा से ऐसे कई वादे करते हैं जो वास्तव में सच नहीं किए जाते। यदि जनता को चुनावों में किए गए वादों और उन्हें पूरा किए जाने के अंतर की देखा जाए तो यह अंतर काफ़ी बड़ी संख्या में पाया जाएगा।**

**बिहार चुनाव में कांग्रेस की रणनीतिक विफलता से उठे मध्यप्रदेश कांग्रेस के अनुभवहीन नेतृत्व पर सवाल**

बिहार विधानसभा चुनाव के ताज़ा परिणामों ने कांग्रेस संगठन की रणनीतिक कमजोरियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। राहुल गांधी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों के बावजूद पार्टी उस भरोसे पर खरी नहीं उतर सकी, जिसकी अपेक्षा राष्ट्रीय नेतृत्व ने की थी। खासकर मध्यप्रदेश कांग्रेस के वे प्रमुख नेता, जिन्हें

बिहार में चुनाव संचालन, बूथ प्रबंधन, प्रचार-रणनीति और संगठनात्मक तालमेल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वे इस परीक्षा में पूरी तरह असफल साबित हुए। परिणाम यह रहा कि जहाँ 200 से अधिक विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ा, वहीं उसे केवल 5 सीटों पर विजय मिल सकी। यह स्थिति कांग्रेस के लिए न केवल निराशाजनक है बल्कि अत्यंत आवश्यक होती है, लेकिन एमपी कांग्रेस की टीम इन स्थानीय वास्तविकताओं को समझने में विफल रही। प्रचार से लेकर उम्मीदवार चयन तक कई स्तरों पर रणनीतियाँ जमीन से दूर रहीं। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी विफलता बूथ प्रबंधन और मतदाता संपर्क के मोर्चे पर देखने को मिली। मध्यप्रदेश कांग्रेस द्वारा भेजी गई टीमों ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से अनुभवी नेताओं के अनुभव का उपयोग नहीं किया। कमलनाथ, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पी. चिदंबरम, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता चुनाव प्रबंधन, संगठन निर्माण और संकट स्थितियों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। कमलनाथ स्वयं देश के उन चुनिंदा नेताओं में रहे हैं जिन्होंने हमेशा चुनाव अभियानों में संगठन को मजबूती देने और बूथ स्तर तक

संगठनात्मक ढांचे की कमजोरियों की भी स्पष्ट संकेतक है।

**मध्यप्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की रणनीति क्यों हुई फेल**

मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पार्टी के कई प्रमुख चेहरों को बिहार चुनाव में विशेष जिम्मेदारियाँ दी गई थीं। बिहार जैसे सामाजिक-राजनीतिक रूप से जटिल प्रदेश में स्थानीय समीकरणों, जातीय गठजोड़ों और क्षेत्रीय मुद्दों की समझ

अपेक्षित समन्वय नहीं किया। कई क्षेत्रों में प्रचार कार्यक्रम तो हुए, लेकिन वे न तो जनसरोकारों को छू सके और न ही मतदाताओं में विश्वास पैदा कर सके। परिणामस्वरूप कांग्रेस का जनाधार और भी संकुचित होता गया।

**बड़े नेताओं का अनुभव क्यों नहीं लिया गया?**

इस चुनाव में कांग्रेस की एक और बड़ी कमी यह रही कि पार्टी ने अपने वरिष्ठ और

रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा उपचुनाव से लेकर निकाय और लोकसभा चुनावों में उन्होंने जिस तरह की जिम्मेदारियों को निभाया, वह कांग्रेस के भीतर एक मिसाल मानी जाती है। लेकिन बिहार चुनाव में उनकी विशेषज्ञता को दरकिनार कर दिया गया। अन्य वरिष्ठ नेताओं के विचार और सुझाव भी रणनीति में परिलक्षित नहीं हुए। यह अनदेखी कांग्रेस के चुनाव अभियान में

स्पष्ट रूप से दिखाई दी न तो संदेश स्पष्ट था, न नेतृत्व केंद्रित और न रणनीति में समन्वय।

**जिद और गैर जिम्मेदाराना नीतियाँ पार्टी पर भारी**

कांग्रेस की बिहार में पराजय के पीछे एक कारण यह भी माना जा रहा है कि पार्टी के कुछ नेताओं की जिद और मनमानी नीतियों ने पूरे चुनाव को नुकसान पहुँचाया। टिकट वितरण में स्थानीय समीकरणों की अनदेखी, कुछ नेताओं का गुटीय राजनीति में उलझना, और मैदान में वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों के बजाय *केंद्रीयकृत निर्णयों* पर निर्भरता ये सभी कारण कांग्रेस को भारी पड़े। पार्टी का न तो चुनावी संदेश प्रभावशाली रहा, न वह जनता को यह भरोसा दिला सकी कि वह एक मजबूत विकल्प बनकर उभर सकती है। इकट्ठे होकर लड़े बिना जीत की उम्मीद करना एक भ्रम था, जिसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा।

**राहुल गांधी के भरोसे पर खरे क्यों नहीं उतर सके नेता ?**

राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन को नए सिरे से मज़बूत करने के तहत अलग-अलग राज्यों के नेताओं को अन्य राज्यों में जिम्मेदारियाँ सौंपने की रणनीति विकसित की थी। उनका उद्देश्य था कि संगठनात्मक अनुभव का परस्पर आदान-प्रदान हो और कांग्रेस एक सामूहिक शक्ति के रू प में मजबूत बने।

**बिहार में कांग्रेस के भविष्य के लिए क्या सीख ?**

बिहार चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस को कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। स्थानीय नेतृत्व को प्राथमिकता देना होगी। उम्मीदवार चयन में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों की अनदेखी नहीं की जा सकती। बूथ प्रबंधन की वैज्ञानिक प्रणाली विकसित करनी होगी। बड़े नेताओं के अनुभव को नज़रअंदाज़ करना भविष्य में भारी पड़ेगा। संगठन को ज़मीनी स्तर पर मजबूत किए बिना चुनाव जीतने का कोई शॉर्टकट नहीं।

बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार केवल सीटों की हार नहीं है, बल्कि यह उसकी रणनीतिक कमजोरी, संगठनात्मक शिथिलता और नेतृत्व के स्तर पर समन्वय की विफलता का परिणाम है। मध्यप्रदेश कांग्रेस के नेताओं से जो जिम्मेदारी की अपेक्षा थी, वे उस पर खरे नहीं उतर सके। राहुल गांधी ने जिन नेताओं पर भरोसा जताया, उनका प्रदर्शन उस भरोसे के अनुरूप नहीं रहा। अगर कांग्रेस भविष्य में अपने राजनीतिक अस्तित्व को मज़बूत करना चाहती है, तो उसे अपनी रणनीतियों में पारदर्शिता, सामूहिक नेतृत्व, वरिष्ठों के अनुभव का उपयोग और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ सशक्त संवाद स्थापित करना ही होगा। बिहार की हार इस बात का संकेत है कि कांग्रेस को आत्ममंथन के साथ-साथ आत्म सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे अन्यथा ऐसी हारें पार्टी के जनाधार को और कमजोर करती जाएँगी।

# छत्तीसगढ़ में मोस्ट वान्टेड नक्सली हिडमा के एनकाउंटर से उठे सवाल

## हिडमा ढेर, लेकिन रहस्य गहराए, क्या साजिश के तहत हुआ एनकाउंटर?

विजया पाठक

18 नवंबर को लाल आतंक का सबसे दुर्दांत शख्स माडवी हिडिमा उर्फ देवा मारा गया। छत्तीसगढ़ में मोस्ट वान्टेड नक्सली और नक्सली संगठन की रणनीतिक रूप से सक्रिय कमांडर हिडमा के एनकाउंटर ने राज्य की कानून-व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन अभियान और पुलिस-प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबे समय से राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बने हिडमा की मौत को एक बड़ी सफलता के रूप में पुलिस ने प्रस्तुत किया, लेकिन इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी, तथ्यगत शंकाओं और गोपनीय परिस्थितियों ने इस एनकाउंटर के पीछे की वास्तविकता पर बहस को जन्म दिया है। हिडमा लंबे समय से नक्सली गतिविधियों की मुख्य समन्वयक माना जाता रहा है। कई जिलों में उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, विस्फोटक निर्माण, पुलिस

> छत्तीसगढ़ में मोस्ट वान्टेड नक्सली और नक्सली संगठन की रणनीतिक रूप से सक्रिय कमांडर हिडमा के एनकाउंटर ने राज्य की कानून-व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन अभियान और पुलिस-प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बलों पर घात लगाकर हमला सहित कई गंभीर मामले दर्ज थे। ऐसे में उसकी मौत पुलिस के लिए उपलब्धि मानी जा सकती है। परंतु यह घटनाक्रम इतना सीधा नहीं रहा। प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि पुलिस को फायर करना आवश्यक हो गया? यदि गिरफ्तारी संभव थी तो उसे जिंदा पकड़ने का विकल्प क्यों नहीं अपनाया गया? गोली कमर के उपर वाले हिस्से में क्यों दागी गई, चर्चा का विषय बना हुआ है। आमतौर पर आत्मसमर्पण की स्थिति में पुलिस घातक हिस्सों पर गोली नहीं चलाती, बल्कि ऐसी जगह फायरिंग करती है जहाँ जान बच सकती है। हिडिबा को जिस स्थान पर गोली लगी, उसने परिस्थितियों को और संदिग्ध बना दिया। सूत्रों की माने तो हिडिमा तेलंगाना में आत्मसमर्पण करने वाला था। बस्तर आई जी सुन्दराज ने हिडिमा को छत्तीसगढ में आत्मसमर्पण के लिए तैयार भी कर लिया था पर शायद प्रदेश के गृहमंत्री यह नहीं चाहते थे। हिडिमा जैसे दुर्दांत नक्सली के आत्मसमर्पण के बहुत मायने निकल सकते थे -

- देश भर में लाल आतंक का नेटवर्क एक झटके में टूट जाता।
- पैसों और हथियारों से नक्सल नेटवर्क की कौन मदद करता था।
- पिछले 25 सालों में माडवी हिडिमा उर्फ देवा द्वारा मारे गए 150 से उपर फोर्सेस के लोगों के पीछे असली व्यक्ति कौन था?
- झीरम घाटी का असली मास्टर माइंड कौन है?
- भारत में नक्सलवाद को चलाने वाले किरदार कौन है?
- बड़ा सवाल यह है कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या सिर्फ आलाकमान के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए एनकाउन्टर

करवाया या इसके पीछे कोई साजिश थी?

▶▶ क्या हिडिमा के आत्मसमर्पण करने से बस्तर के आदिवासी हमेशा के लिये लाल आतंक से दूर चले जाते?

**आंध्रप्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर संदेह**

चर्चा है कि आंध्र पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ रेड्स चलाईं। इन रेड्स में कृष्णा, एलुरू, काकीनाडा, एनटीआर विजयवाड़ा और कोनसीमा जिलों में छिपे माओवादियों को ढूंढ-ढूंढकर पकड़ा गया। कुल 50 माओवादी कैडर गिरफ्तार किए गए, जो अपने आप में बेहद बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। सुकमा इलाके में जिस माओवादी कमांडर हिडमा की पत्नी और उसके साथियों का एनकाउंटर हुआ, वह सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है. ऑपरेशन के दौरान जवानों ने घने जंगलों में छिपे नक्सलियों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों ओर से जोरदार फायरिंग हुई और इसमें हिडमा की पत्नी समेत कई नक्सली ढेर हो गए। मौके से हथियार, गोला-बारूद और नक्सली सामग्री भी बरामद की गई। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस कार्रवाई से माओवादी संगठन की रीढ़ और कमजोर पड़ गई है, क्योंकि ये सभी हिडमा के भरोसेमंद और सक्रिय कैडर माने जाते थे।

**गिरफ्तार कैडरों में कई बड़े नाम शामिल हैं**

**समर्पण का विकल्प कितना मजबूत था?**

चर्चा यह भी है कि हिडमा बीते कुछ

> नक्सल विरोधी अभियानों से जुड़े लोगों के हवाले से यह दावा सामने आया कि उसके आत्मसमर्पण की संभावना तेजी से बढ़ रही थी। यही बिंदु आलोचना का केंद्र है यदि हिडमा जीवित पकड़ा जाता, तो नक्सली नेटवर्क के बड़े हिस्से की जानकारी उजागर हो सकती थी। हथियार सप्लाय चेन, प्रशिक्षण तंत्र, वित्तीय नेटवर्क, स्थानीय समर्थन और माओवादी नेतृत्व की गतिविधियों का अंदरूनी डेटा मिल सकता था। इसी कारण आलोचना के स्वर बुलंद हुए कि कहीं उद्देश्यपूर्ण ढंग से उसे जिंदा न रखने का निर्णय तो नहीं लिया गया?

**केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सामने उपलब्धि प्रदर्शित करने के लिए छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा द्वारा इसे एक त्वरित सफलता के रूप में पेश किया गया। विपक्ष दावा कर रहा है कि यह एनकाउंटर नक्सल विरोधी नीति की रणनीति से ज्यादा राजनीतिक लाभ का साधन बन गया।**

नेटवर्क के बड़े हिस्से की जानकारी उजागर हो सकती थी। हथियार सप्लाय चेन, प्रशिक्षण तंत्र, वित्तीय नेटवर्क, स्थानीय समर्थन और माओवादी नेतृत्व की गतिविधियों का अंदरूनी डेटा मिल सकता था। इसी कारण आलोचना के स्वर बुलंद हुए कि कहीं उद्देश्यपूर्ण ढंग से उसे जिंदा न रखने का निर्णय तो नहीं लिया गया?

**राजनीतिक बयानबाजी और आरोपों की श्रृंखला**

करने वाले डेटा तक पहुंचने का अवसर मुख्यमंत्री और केंद्रीय एजेंसियों ने खो दिया। यहाँ तक आरोप लगे कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सामने उपलब्धि प्रदर्शित करने के लिए छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा द्वारा इसे एक त्वरित सफलता के रूप में पेश किया गया। विपक्ष दावा कर रहा है कि यह एनकाउंटर नक्सल विरोधी नीति की रणनीति से ज्यादा राजनीतिक लाभ का साधन बन गया।

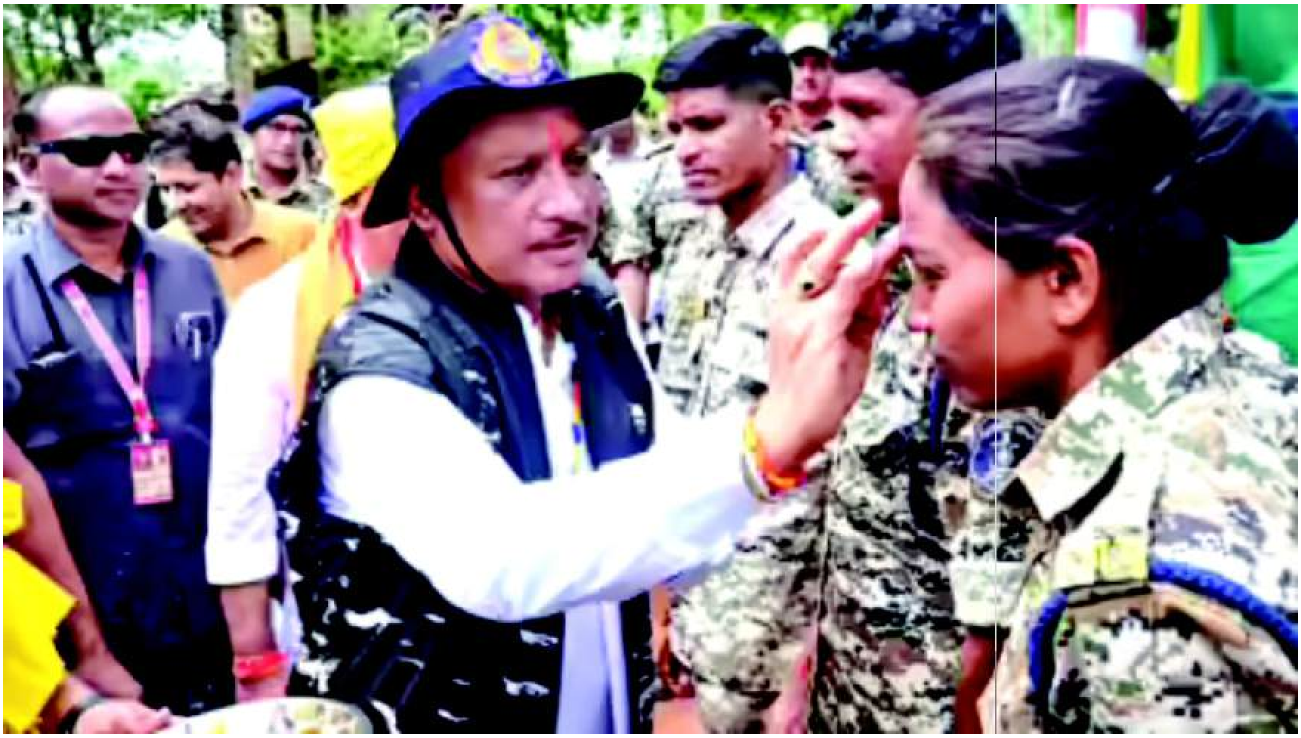

महीनों से आत्मसमर्पण के बारे में बातचीत कर रहा था या सुराग तलाशने वाली एजेंसियों के संपर्क में था। इस तथ्य की आधिकारिक पुष्टि न तो पुलिस ने की और न ही राज्य के गृहमंत्रालय ने। लेकिन नक्सल विरोधी अभियानों से जुड़े लोगों के हवाले से यह दावा सामने आया कि उसके आत्मसमर्पण की संभावना तेजी से बढ़ रही थी। यही बिंदु आलोचना का केंद्र है यदि हिडमा जीवित पकड़ा जाता, तो नक्सली

एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सबसे आगे रहे। उन्होंने पूछा कि अगर हिडमा को घेरा गया था, तो उसे आत्मसमर्पण का अवसर क्यों नहीं दिया गया? दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि पुलिस ने गोली मारी, तो गैर-घातक हिस्सों में क्यों नहीं मारी? उनका तर्क है कि सूचना देने, नेटवर्क उजागर करने और नक्सल संगठन की रणनीतियों का पर्दाफाश

**मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले दो साल में प्रदेश से नक्सलवाद अंतिम सांसे ले रहा है।**

हिडमा के एनकाउंटर को लेकर सबसे ज्यादा संदेह प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा पर हो रहा है। आरोप लग रहे है कि क्या वाहवाही लूटने के चक्कर में हिडमा का आत्मसमर्पण नहीं, एनकाउंटर करवाया गया।

**पुलिस का पक्ष और सरकारी दलीलें**

दूसरी ओर पुलिस और गृह विभाग अपनी दलीलों में यह कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों पर उस समय हमला हुआ। जवाबी फायरिंग में हिडमा मारा गया। कोई आत्मसमर्पण जैसी परिस्थिति उस समय उपलब्ध नहीं थी, ऑपरेशन जोखिमपूर्ण था और त्वरित कार्रवाई आवश्यक थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, क्षेत्र जंगल, पहाड़ी ढलानों और घने झाड़ियों वाला था, जहां टकराव की स्थिति में कोई रणनीतिक वार्ता संभव नहीं हो सकती थी। सुरक्षा विशेषज्ञों का मत है कि नक्सल संगठन में हिडमा की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वह नए युवाओं की भर्ती में सक्रिय था, हथियारों की खेप और विस्फोटक सामग्री के परिवहन में सहयोगी था, महिला विदेशी मीडिया से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। इन बिंदुओं से स्पष्ट है कि उसका जीवित रहना नक्सल संगठनों के लिए रणनीतिक लाभ बना हुआ था। एनकाउंटर के बाद बड़ा प्रश्न यही है कि क्या पुलिस ने एक ऐसे अवसर को गंवा दिया, जहाँ जमीन-स्तर पर गहरी सूचनाएँ मिल सकती थीं? यह वही प्रश्न है जिसने इस पूरे मामले को एक गहन बहस का विषय बना दिया। यदि कोई उच्च स्तरीय पूछताछ होती, तो संभवतः उस नेटवर्क तक पहुँचा जा सकता था जो दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसी घटनाओं का आधार बनता रहा है। देखा जाये तो स्पष्ट तथ्य अब तक सार्वजनिक नहीं हैं, इसलिए आवश्यक है कि स्वतंत्र जाँच समिति का गठन हो, ऑपरेशन के वीडियो डेटा या वायरलेस रिकॉर्डिंग

एनकाउंटर के बाद बड़ा प्रश्न यही है कि क्या पुलिस ने एक ऐसे अवसर को गंवा दिया, जहाँ जमीन-स्तर पर गहरी सूचनाएँ मिल सकती थीं? यह वही प्रश्न है जिसने इस पूरे मामले को एक गहन बहस का विषय बना दिया। यदि कोई उच्च स्तरीय पूछताछ होती, तो संभवतः उस नेटवर्क तक पहुँचा जा सकता था जो दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसी घटनाओं का आधार बनता रहा है। देखा जाये तो स्पष्ट तथ्य अब तक सार्वजनिक नहीं हैं, इसलिए आवश्यक है कि स्वतंत्र जाँच समिति का गठन हो।

एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सबसे आगे रहे। उन्होंने पूछा कि अगर हिडमा को घेरा गया था, तो उसे आत्मसमर्पण का अवसर क्यों नहीं दिया गया? दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि पुलिस ने गोली मारी, तो गैर-घातक हिस्सों में क्यों नहीं मारी?

सार्वजनिक की जाए, एसेस्कलेशन मॉडल का अध्ययन हो। हिडमा की मौत से प्रशासनिक और सुरक्षा लाभ तो दिखाई देते हैं, परंतु इसके साथ यह भी तथ्य है कि उसकी गिरफ्तारी राज्य और केंद्र की संयुक्त एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण मोड़ दे सकती थी। इस एनकाउंटर के पीछे की प्रक्रिया, निर्णय-समय, परिस्थितियाँ और कमांड-स्ट्रक्चर अभी भी धुंध में छिपे हुए हैं। मामले को सिर्फ सफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि नक्सल उन्मूलन रणनीति की सामरिक और दीर्घकालिक दृष्टि से भी परखा जाना चाहिए। यदि इस घटना से राजनीतिक लाभ जुटाया गया, तो यह नक्सल समस्या के मूल समाधान की दिशा में बाधा बन सकता है। दूसरी ओर, यदि परिस्थितियाँ सचमुच उतनी ही जोखिमपूर्ण थीं जितना पुलिस दावा कर रही है, तो एनकाउंटर की कार्रवाई को सुरक्षित रणनीतिक निर्णय भी माना जा सकता है।

**छत्तीरसगढ़ में मार्च 2025 तक होना है नक्सलवाद का खात्मा**

कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़मा को सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। माड़वी हिडमा की मौत देश में नक्सलवाद के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है और इससे नक्सलियों की सैन्य क्षमताएं कमजोर होंगी। हाल के वर्षों में देश में हुई हर बड़ी नक्सली घटना के पीछे माड़वी हिड़मा का ही दिमाग माना जाता है। नक्सलवाद के खिलाफलड़ाई में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सुरक्षाबलों ने छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हुई एक मुठभेड़ में देश के सबसे खतरनाक और वांछित नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा को ढेर कर दिया। माओवादियों को यह हाल के वर्षों में लगा सबसे बड़ा झटका है और दावा किया जा रहा है कि माड़वी हिडमा की मौत के बाद अब देश में नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है।

**कौन था माड़वी हिड़मा ?**

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जन्में माड़वी हिड़मा ने 16 साल की उम्र में ही हथियार उठा लिए थे और बतौर कैडर शुरुआत करके माड़वी हिड़मा बीते दो दशकों में प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) में कई अहम पदों पर रहा। हिड़मा कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था और उस पर सरकार ने एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। माड़वी हिड़मा सीपीआई माओवादियों की बटालियन नंबर एक का कमांडर था, जो नक्सलियों की सबसे खतरनाक सैन्य टुकड़ी मानी जाती है। हिडमा दंडकारण्य क्षेत्र के घने जंगलों में रहता था और उसे अबूझमाड़ और सुकमा-बीजापुर के वन क्षेत्रों की काफी जानकारी थी। यही वजह थी कि कई कोशिशों के बाद भी हिडमा लंबे समय तक सुरक्षाबलों से बचता रहा। हिडमा फिलहाल बस्तर दक्षिण इलाके में सक्रिय था।

**दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ पर हमले समेत कई बड़े हमलों का था मास्टरमाइंड**

हिड़मा कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल के वर्षों के अधिकतर बड़े नक्सली हमलों में उसकी संलिप्तता था फिर चाहे वो साल 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफपर हुआ हमला हो, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवानों बलिदान हुए थे या फिर दरभा घाटी में झीरम घाटी का हमला, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूरे कांग्रेस नेतृत्व को खत्म कर दिया गया था। साल 2017 में सुकमा में हुए दो हमलों, जिनमें 37 जवानों की मौत हुई थी और 2021 के बीजापुर में तर्रेम हमले में भी माड़वी हिड़मा का नाम सामने आया था। सुरक्षाबलों का दावा है कि अप्रैल 2025 में कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर हुई मुठभेड़ में हिड़मा बाल-बाल बच गया था। उस मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए थे। कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़मा को सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। माड़वी हिड़मा की मौत देश में नक्सलवाद के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है और इससे नक्सलियों की सैन्य क्षमताएं कमजोर होंगी। माओवादियों को यह हाल के वर्षों में लगा सबसे बड़ा झटका है और दावा किया जा रहा है कि माड़वी हिड़मा की मौत के बाद अब देश में नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरूहो सकती है।

**नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू**

बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज पी का कहना है कि माड़वी हिड़मा की मौत नक्सलवाद के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि कई कुख्यात माओवादी हाल के समय में ढेर हो चुके हैं और कई मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। अब बाकी बचे नक्सली कमांडरों से भी आत्मसमर्पण की अपील की जाएगी और जो अभी भी हिंसा के रास्ते पर चलेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिडमा की मौत से बस्तर क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। सरकार ने साल 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य तय किया और माड़वी हिड़मा की मौत उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हिडमा की मौत के साथ ही देश में नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है।

अन्नदाता
मध्यप्रदेश शासन
पराली न जलाएं, धरती और जीवन बचाएं
उपजाऊ शक्ति में वृद्धि | प्रदूषण से मुक्ति | अर्थव्यवस्था को गति
मिट्टी के रूप में मिले वरदान को नष्ट होने से बचाएं
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
ये विकल्प अपनाएं
हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम यंत्र का उपयोग
हैप्पी सीडर और सुपर सीडर का उपयोग कर सीधी बोनी
रीपर से कटाई के बाद जीरो टिलेज मशीन से सीधे बोनी
बेलर मशीन का उपयोग कर धान की पराली और मक्के के तने के बेल्स बनाएं
धान की पराली का प्लेट्स, ब्रिक्स और बायो फर्टिलाइजर के निर्माण में उपयोग
JFARM SERVICES
पराली हटाने के यंत्र
farmer.mpdage.org
पर खरीदें या
JFarm Services app
के जरिए
किराये से प्राप्त करें
प्राकृतिक खेती को अपनाएं
मिट्टी की सतह पर सूक्ष्म जीवों के बढ़ावे से मिट्टी की उर्वर शक्ति में वृद्धि
रासायनिक पदार्थों से मुक्त होने से कैंसर जैसी घातक बीमारियों से मुक्ति
प्राकृतिक खेती से उत्पादन में कोई कमी नहीं
आइये, स्वस्थ मिट्टी, स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के लिए पराली न जलाने का प्रण लें....

वस्त्र मंत्रालय
MINISTRY OF TEXTILES
MPIDC
इन्वेस्ट मध्यप्रदेश
उद्योग एवं रोज़गार वर्ष 2025
मध्यप्रदेश के कपास उत्पादक किसानों की समृद्धि का द्वार
देश का सबसे बड़ा
'पीएम मित्र' पार्क
धार, मध्यप्रदेश
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
का 5F विज़न
फार्म टू फाइबर । फाइबर टू फैक्ट्री । फैक्ट्री टू फैशन । फैशन टू फॉरेन
कम्पलीट वैल्यू चेन @ वन डेस्टिनेशन
कताई से लेकर सिलाई तक पूरी प्रक्रिया के लिये
एकीकृत मेगा टेक्सटाइल पार्क
पार्क क्षेत्र - 2,158 एकड़
₹ 20 हजार करोड़ का निवेश सुनिश्चित
3 लाख लोगों को रोज़गार
टेक्सटाइल के क्षेत्र में लब्ध-प्रतिष्ठित 91 कंपनियों को
निवेश प्रस्ताव के अनुरूप भूमि आवंटित
फार्म से फॉरेन तक मध्यप्रदेश का वस्त्र उद्योग
मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
आकल्पन: म.प्र. माध्यम/2025

# दृढ़ संकल्प से ही शराबबंदी संभव!

**रघु ठाकुर**

बिहार चुनाव में देश और दुनिया के अनेकों मुद्दे चर्चित रहे, कौनसा समूह कितने रूपए बाटेंगा, कौन क्या देगा, पर शराबबंदी पर कोई चर्चा नहीं हुई। जिस प्रदेश की सरकार ने और विशेषतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का साहसिक निर्णय दिया था, जिसको लेकर बिहार के हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हुई थी। जस्टिस काटजू से लेकर विशिष्ट कहे जाने वाले वकीलों और सज्जनों ने शराबबंदी को अव्यवहारिक बताकर उसका विरोध किया था, परंतु नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हर आलोचना को सहा और उसका उत्तर दिया पर अपने निर्णय पर अडिग रहे। हमारे देश के तथागत वामपंथी प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता का दावा करने वाली जमातें जो उस समय नीतीश कुमार को गांधी का दूसरा अवतरण बता रही थीं, उन्हें अगला प्रधानमंत्री बता रही थीं, हालांकि वे भी बाद में उनके खिलाफहो गई। शायद इसलिए कि उस समय कांग्रेस नीतीश कुमार के पक्ष में थी और अब नहीं। दुनिया की आर्थिक शक्तियों के द्वारा संचालित होने वाला धर्मनिरपेक्षता का अभियान का स्वर भी बदल गया था, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीतिक पाला बदलकर एनडीए के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए थे और उसके बाद से शराबबंदी जैसा महत्वपूर्ण कदम अचर्चित हो गया। जब समर्थक ही आलोचक बन गये तो स्वाभाविक था कि वे तारीफ कैसे करते और तारीफ करते तो राजनीतिक नुकसान होता और शायद वैश्विक फंडिंग बंद हो जाती।

**आज स्थिति यह हो रही है कि गांव-गांव में शराब माफिया और शराब के फुटकर विक्रेताओं की जमात खड़ी हो गई है, गांव के गरीब बेरोजगार बच्चों को नशे के दुकानदार और माफिया मोटर साइकिल दे रहे हैं, वह गांव-गांव में जाकर नशा बेचते हैं।**

इस चुनाव के बीच 2 नवंबर को मध्यप्रदेश के संस्कृति मंत्री ने एक बयान दिया कि बिहार में शराबबंदी लागू है और माफिया घर-घर शराब पहुंचा रहे हैं। मुझे नहीं पता की संस्कृति मंत्री एनडीए के पक्ष में हैं

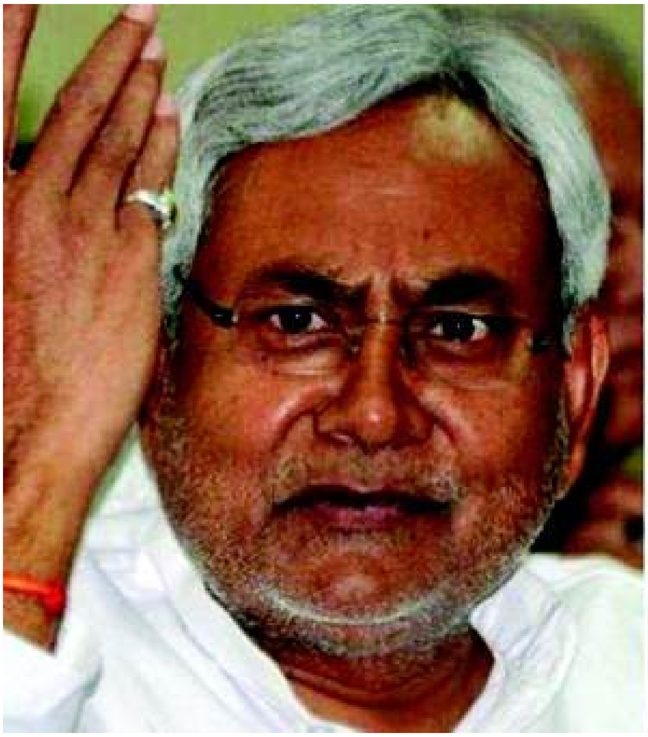

या खिलाफ, परंतु उनके बयान से बिहार में एनडीए के खिलाफ एक मुद्दा जरूर लोगों को दे दिया था कि अब एनडीए के मंत्री मान रहे है कि माफिया घर-घर शराब पहुंचा रहे हैं, तो शराबबंदी कैसी? और एनडीए की सरकार शराब माफिया से मिली हुई है। हालांकि इसके बावजूद भी यह मुद्दा कोई चुनाव के लिए बड़ा सवाल नहीं बन सका।

मैं संपूर्ण शराबबंदी के पक्ष में हूं और मानता हूं कि महात्मा गांधी की यह इच्छा और निर्देश था कि शराबबंदी होना चाहिए। जब मैं शराबबंदी की बात रहा हूं तो सारे नशे की बात कह रहा हूं। समाज में हर प्रकार के नशे की बंदी होना चाहिए। नशा न केवल एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करता है बल्कि समूचे समाज परिवार को उजाड़ता है। गरीब व्यक्ति जब नशा करते हैं तो वह अपना ही घर बर्बाद करते हैं, नशे की गिरफ्त में आकर कर्ज लेते हैं, जमीन मकान संपत्ति बेच देते हैं, बच्चों और बीवी के साथ मारपीट, गाली गलौज करते हैं, उन्हें भी नशा करना सिखाते हैं और अपने वोट को भी नशे के लिए बेच देते हैं। आज स्थिति यह हो रही है कि गांव-गांव में शराब माफिया और शराब के फुटकर विक्रेताओं की जमात खड़ी हो गई है, गांव के गरीब बेरोजगार बच्चों को नशे के दुकानदार और माफिया मोटर साइकिल दे रहे हैं, वह गांव-गांव में जाकर नशा बेचते हैं, जरूरत होती है तो उधार भी दे देते हैं बाद में मारपीट कर वसूल करते हैं, जमीन गिरवी रखवा लेते हैं इससे गांव के गांव कर्जदार बन गए, नशा करने वाले माफियाओं के बंधक बन गए, यह माफिया राजनैतिक दलों और नेताओं को भारी चंदा देते हैं, गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था करवा देते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति के नियंत्रक बन जाते हैं। नशे का सबसे ज्यादा प्रभाव घरों की महिलाओं पर पड़ता है, उन्हें कितना अपमान, मारपीट सहना होती है इसकी कल्पना करना भी कठिन है।

मैं जिस पार्टी (लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी) का नेतृत्व करता हूँ जैसे चंद वैचारिक दलों को छोड़ दें अन्यथा लगभग सभी सत्ताधारी और मुख्य विपक्षी दलों की राजनीति के दिये नशा माफियाओं के चंदे के तेल से जलते हैं। अक्सर सरकार और राजनीति दल यह तर्क देते हैं कि शराब और नशा राजस्व का बड़ा माध्यम है परंतु यह सत्य नहीं है। महात्मा गांधी कहते थे कि शराब अनैतिक है और सरकारों को अनैतिक व्यवसाय नहीं करना चाहिए। क्या सरकार अपने राजस्व के नाम पर वेश्यावृत्ति को भी धंधा मान लेगी और अपने आय के नाम पर चकला घर चलाऐगी? नशे की

**नशा न केवल एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करता है बल्कि समूचे समाज परिवार को उजाड़ता है। गरीब व्यक्ति जब नशा करते हैं तो वह अपना ही घर बर्बाद करते हैं, नशे की गिरफ्त में आकर कर्ज लेते हैं।**

पार्कों में बच्चे नशे की सिगरेट लेकर हर प्रकार के नशे करते पाये जाते हैं और सार्वजनिक स्थान सार्वजनिक अपराध के

गिरफ्त इतनी बढ़ गई है कि बच्चे, छात्र और बेटियां भी इसके प्रभाव में आ चुकी हैं स्कूलों के बच्चों के लिए 10-15 रूपये की कीमत वाले शराब के बच्चे पाउच बनाए गए और बेचे जा रहे हैं जो स्कूलों के आसपास दुकानों, होटलों पर आसानी से उपलब्ध हैं। छोटे-छोटे बच्चे घर में माता-पिता से एवं बाहर के वातावरण से नशा करना सीख रहे हैं। नगरों और शहरों में भी बेटियां प्रगतिशीलता के नाम पर शराब, सिगरेट, गांजे का सात्विक प्रयोग करने लगी और सारी वर्जनाएं टूट रही हैं। सार्वजनिक स्थान बन गए हैं। पुलिस और प्रशासन के लिए भी यह भ्रष्टाचार की आय के स्थाई निर्बाध और संस्थागत माध्यम बन गए।

एक पुलिस के थानेदार के पास उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ की संपत्ति पाई जाती है, रतलाम में एक नशे के अपराधी को भगाने के लिए पुलिस 50 लाख की रिश्वत लेती है और समूचे देश में न जाने इस प्रकार की कितनी घटनाएं प्रतिदिन अखबारों में छपती हैं। राजनीतिक घात प्रतिघात का मुद्दा तो नशा बनता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने उड़ता पंजाब यानी नशे में उड़ता पंजाब

**मध्यप्रदेश तो शराब की बिक्री एवं पीने के मामले में शीर्ष पर है। जहां पिछले दो वर्षों में 86 प्रतिशत की वृद्धि शराब बिक्री में हुई है यानी 456 लाख लीटर की खपत हुई। राजस्थान में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई यानी 304 लाख लीटर की शराब पिलाई गई।**

का मुद्दा बनाया और सरकार बना ली थी। भाजपा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की

शराब नीति का मुद्दा विधानसभा चुनाव में बनाया और सत्ता हथियाईं। इसका मतलब साफ है कि आम जनमानस ने जहां कहीं भी नशाबंदी, शराबबंदी की घोषणा की गई उन्हें जन समर्थन दिया है। आंध्र प्रदेश में स्वर्गीय रामाराव, हरियाणा में स्वरूचौधरी देवीलाल को शराबबंदी की घोषणा के बाद समाज और खासकर महिलाओं का भारी समर्थन मिला था। जो लोग शराब के समर्थन के लिए नकली शराब या जहरीली शराब का तर्क देते हैं वह झूठा तर्क देते हैं और नशे का बचाव करते हैं। 14-15 करोड़ की आबादी के बिहार में 100-50 लोग नकली या जहरीली शराब से मर जाते हैं तो यह कोई उल्लेखनीय घटना नहीं है। जहां दुर्घटनाओं में 80,000 लोग मर जाते हैं वहां 8-10 निर्दोष मर जाये, वहां 100-50 लोगों को नकली शराब से मौत हो भी जाए तो इसे घटना नहीं माना जा सकता।

यह दुखद है कि जहाँ दुनिया में शराब की खपत घट रही है वहीं भारत में इसकी खपत बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका यूरोप और चीन के बाजारों में शराब निर्माता जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर 75 प्रतिशत तक गिर गए हैं और शराब उद्योगों को 74 लाख करोड़ का घाटा हुआ है, यानी भारत के बजट से लगभग दुगना। जबकि भारत को गांधी का देश कहा जाता है। देश में पिछले लगभग बीस वर्षों में शराब की खपत लगभग तीन गुना बढ़ गई है। भारत का बाजार 4800 अरब यानी 5 लाख करोड़ रूपए का हो गया है और प्रमुख शराब निर्माता कंपनियों के दाम 14 गुना तक बढ़ गए हैं। वर्ष 2005 में प्रति व्यक्ति वार्षिक शराब की खपत 2.4 लीटर थी जो अब 6 लीटर से अधिक हो चुकी है। देसी ब्रांड शराब कंपनियों के शेयर 14 गुना तक बढ़ गए हैं, तिलक नगर इंडस्ट्रीज का 2021 में एक शेयर का दाम 34 रुपए 70 पैसे था जो अक्टूबर 25 में 528 रूपये का यानी 15 गुना, रेडको खेतान का शेयर जो 616 रूपए का था वह बढ़कर 3135 का हो गया है और इसी प्रकार अन्य शराब निर्माण कम्पनियों के दाम बढ़ गए।

मध्यप्रदेश तो शराब की बिक्री एवं पीने के मामले में शीर्ष पर है। जहां पिछले दो वर्षों में 86 प्रतिशत की वृद्धि शराब बिक्री में हुई है यानी 456 लाख लीटर की खपत हुई। राजस्थान में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई यानी 304 लाख लीटर की शराब पिलाई गई। जो लोग शराब से आय की बात करते हैं वह भूल जाते हैं कि शराब के मालिक विलासता में जीवन गुजारते हैं और बाद में बैंकों से करोड़ों रूपए लेकर भाग जाते हैं, विजय माल्या का उदाहरण आपके सामने है। जहां तक शराब आय का संबंध है तो समूचे देश में शराब से मात्र 19730 करोड रुपए का राजस्व मिलता है यानी भारत के कुल बजट का एक प्रतिशत भी नहीं, बल्कि 0.30 प्रतिशत, यानी एक प्रतिशत का एक बटा तीन ही मिलता है। इतने से बजट की आपूर्ति के लिए देश के मूल परिवार, समाज, राजनीति और व्यवस्था, भारत के आदि मूल्य, सत्य और ईमानदारी को नष्ट करना क्या देश को भीतर से नष्ट करना नहीं है।

मुझे खुशी होगी कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें 30 जनवरी बापू के बलिदान दिवस पर यह निर्णय करें कि देश में संपूर्ण शराब बंदी लागू की जाये। सरकार दुनिया के कॉर्पोरेट को कोर्पोरेट टैक्स कम कर 5 लाख करोड़ का मुनाफा करा देती है। भारत के उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों रूपए वसूलने की बजाय बट्टे खाते में डालकर माफ कर देती है तो क्या देश की आत्मा को बचाने के लिए 19,000 करोड़ रूपए की तुच्छ रकम के लालच को नहीं छोड़ा जा सकता? संभव है बस संकल्प और दृढ़ता की आवश्यकता है।

# प्रदूषण का समाधान सामुदायिक सहभागिता एवं सरकारी सशक्त से संभव

डॉ. प्रशांत सिन्हा

विश्व प्रदूषण निवारण दिवस एवं राष्ट्रीय प्रदूषण नियन्त्रण दिवस हर वर्ष 02 दिसंबर को मनाया जाता है। यह हमारे पर्यावरण के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण और प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूकता फैलाना एक अवसर है। यह विशेष आयोजन 1989 में पर्यावरण में खतरनाक पदार्थो के उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों और रणनीतियों को उजागर करने के प्रयास के रूप में शुरू हुआ था। भारत में 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वालों की याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इसे तेल, गैस और कोयला खनन से लेकर परिवहन, रसायनिक विनिर्माण, कृषि तक कई उद्योगों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया था। यह दिवस प्रदूषण के खिलाफ सीखने और कारवाई करने का एक विशेष अवसर है। यह हमें सरल परिर्वतन करने की याद दिलाता है जो हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं और बदलाव आते हैं। प्रदूषण हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसका समाधान सामुदायिक सहभागिता के साथ साथ सरकारी सशक्त नीतियों से ही हो सकता है। प्रदूषण के समाधान के लिए सरकारों को नीतियों में सुधार करने की जरूरत है। यही नहीं पर्यावरण के लिए नई नीतियों की आवश्यकता है जो प्रदूषण को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सके और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दे सकें।

**भारत में 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वालों की याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इसे तेल, गैस और कोयला खनन से लेकर परिवहन, रसायनिक विनिर्माण, कृषि तक कई उद्योगों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया था।**

हमें नीतियों को अद्धतित करने की आवश्यकता है ताकि वे वर्तमान समय के अनुकूल हों और नई चुनौतियों का सामना कर सकें। नई तकनीकों का समर्थन करने वालो नीतियां बननी चाहिए जो प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकती है। नीतियों में सुधार का मतलब यह नहीं है कि हमें विकास से मुकाबले में कमी करनी चाहिए बल्कि हमें बेहतर और स्वस्थ विकास के लिए स्थाई समाधान ढूंढना चाहिए। हमें सुनिश्चित करना होगा कि ये सुधार वास्तव में परिणामी हों।

पिछले कुछ दशकों में हुए आर्थिक

विकास से देश लाभान्वित तो हुआ है पर हमने इसकी कीमत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर चुकाई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण नुकसान के चलते हर साल भारतीय अर्थव्यवस्था को 80 अरब डॉलर से ज्यादा की चपत लगती है। ऐसे में टिकाउ विकास का लक्ष्य ऐसी तकनीकों के बदौलत ही हासिल हो सकेगा जो विकास के साथ पर्यावरण भी सहेजे। टिकाउ विकास सुनिश्चित करने के लिए देश को अपने प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ोतरी पर ध्यान देना होगा। साथ ही सभी तरह की पारिस्थितिकी को बचाना होगा। विकास को मापने के पारंपरिक तरीकों से काम नहीं चलेगा। पर्यावरणीय विकास के लिए ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानि ग्रीन जीडीपी इंडेक्स विकसित किया जाना चाहिए।

प्रदूषण का समाधान केवल सरकारी कदमों द्वारा ही संभव नहीं है। इसमें समुदाय के सहभागिता और जागरूकता का महत्वपूर्ण योगदान है। समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण के प्रति जागरूक कर सकते हैं और इन्हें इस समस्या का समाधान में सहायक बना सकते हैं। पहले हमें अपने समुदाय के बीच जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षा अभियानों का आयोजन करना चाहिए। यह शिक्षा अभियान लोगों को प्रदुषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करेगा और उनके कार्यो के प्रभाव को समझने के लिए प्रेरित करेगा। हमें समुदाय में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सामुदायिक परियोजनाओं का समर्थन करना चाहिए। हम ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जब धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से दुनिया हलकान है और भावी पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए। सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी नियम कानून बना रखे हैं। इसे विकास की अंधी दौड़ उन्हें हमेशा ठेंगा दिखाती रही है। ऐसे में निजी स्तर पर लोगों को ग्रीन इकोनॉमी यानि हरित अर्थव्यवस्था को अपनाना होगा। समुदाय केन्द्रित दृष्टिकोण से हम न सिर्फ जागरूकता बढ़ा सकते है बल्कि इस समस्या के समाधान में भी सहायक हो सकते हैं। हमें इस मुहिम में एक जुट होकर प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। ताकि हम एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में बढ़ सकें।

# धामी सरकार के तीन वर्ष : निर्णायक फैसलों की मिसाल और जनता के हित में उठाए ठोस कदम

**विजया पाठक**

उत्तराखण्ड की राजनीति में पिछले तीन साल किसी तेज़ चलती नदी की तरह रहे हैं। उपर से शांत लेकिन भीतर गहरी हलचल लिए हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए, जिन्हें उत्तराखण्ड की विकास यात्रा के नए अध्याय के रूप में देखा जा सकता है। युवा मुख्यमंत्री की कार्यशैली का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि वे कठिन निर्णय लेने से हिचकते नहीं, बल्कि स्थितियों का सीधे सामना करते हुए समस्याओं के मूल में जाकर समाधान तलाशते हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तराखण्ड एक अधिक व्यवस्थित, आत्मविश्वासी और भविष्य के लिए तैयार राज्य के रूप में उभर रहा है।

### भर्ती परीक्षा सुधारों की निर्णायक शुरूआत

राज्य में वर्षों से परीक्षाओं में धांधली का दाग था। युवाओं का मनोबल गिरा हुआ था। सरकार ने इस चिंता को सबसे पहले समझा और निर्णायक रूप से कदम उठाए। पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई कर न केवल नकल माफिया की कमर तोड़ी गई, बल्कि उत्तराखण्ड को देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून भी मिला। धामी सरकार का यह निर्णय युवाओं को स्पष्ट संदेश देता है- मेहनत का सम्मान होगा, नकल का नहीं। उत्तराखण्ड में इसका सीधा असर भी देखने को मिला। भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी आई, विलंबित परीक्षाएँ समय पर पूरी होने लगीं, और युवाओं का भरोसा वापस लौटने लगा।

### सम्मानजनक वातावरण की दिशा में कदम

पहाड़ी राज्य की महिलाएँ दोहरी भूमिका निभाती हैं घर की भी और खेत की भी। ऐसे में उनके सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान को

ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई दीर्घकालिक कदम उठाए। फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बढ़ाने से लेकर महिला हेल्पलाइन को और प्रभावी बनाने तक, मिशन शक्तिको नई गति देने से लेकर स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने तक हर स्तर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम हुआ। विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का संचालन बड़ी राहत लेकर आया। इससे उन गाँवों में भी स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचीं, जहाँ पहुँचना कभी मुश्किल होता था।

**चारधाम और आध्यात्मिक पर्यटन का पुनरूत्थान**

उत्तराखण्ड की आत्मा उसके धार्मिक स्थलों में है। धामी सरकार ने इस आत्मा को मजबूत करने के लिए चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और आधुनिक बनाया। केदारनाथ धाम में चल रहा पुनर्निर्माण कार्य आज देश में मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। बदरीनाथ धाम का मास्टर प्लान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरिद्वार में गंगा तटों और घाटों का नया स्वरूप पर्यटन को विश्व स्तरीय बना रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को और सशक्तबनाना है।

**धामी सरकार का ऐतिहासिक और साहसिक फैसला**

उत्तराखण्ड का नाम इतिहास में दर्ज हुआ जब राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने वाला पहला राज्य बना। यह निर्णय न केवल सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि लैंगिक समानता और आधुनिक शासन की दिशा में भी बड़ा कदम माना गया। विशेषज्ञ समिति बनाकर विस्तृत अध्ययन और संवाद के माध्यम से तैयार किया गया UCC मसौदा धामी सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

**राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास**

उत्तराखण्ड में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने कई उद्योग-अनुकूल नीतियाँ लागू कीं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने राज्य में हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिलाए, जिसका असर आने वाले वर्षों में रोजगार और उद्योग के रूप में दिखेगा। पर्यटन, फार्मा, आयुष, आईटी और खाद्य प्रसंस्करण

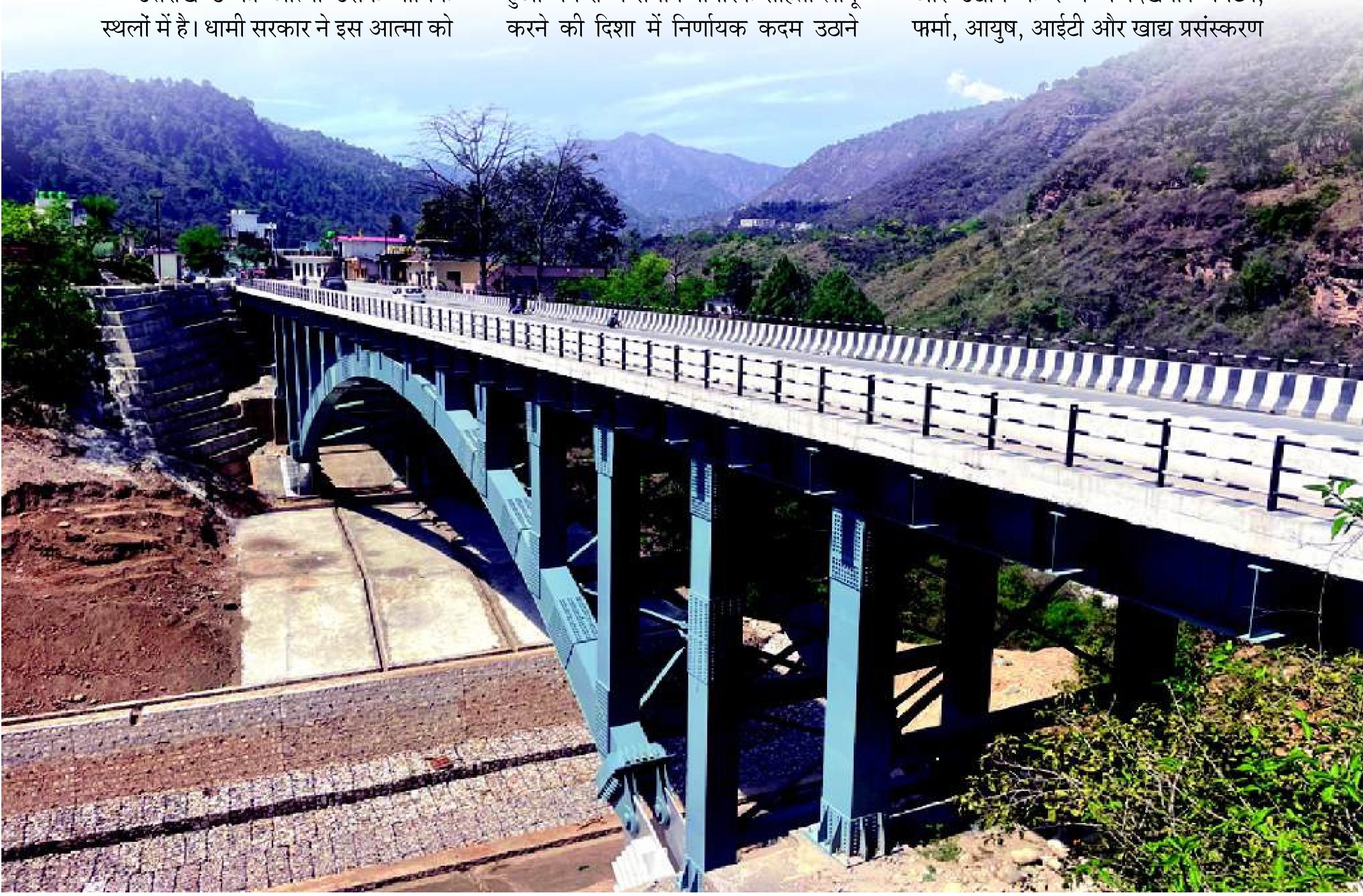

जैसे क्षेत्रों में निवेश के नए मार्ग खुले। सरकार का फोकस पहाड़ी जिले रहे, जहाँ क्लस्टर आधारित उद्योग और स्थानीय उत्पादों के ब्रांडिंग को प्राथमिकता दी गई।

### सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा को नई गति

उत्तराखण्ड में विकास की सबसे बड़ी बाधा हमेशा कठिन भूगोल रहा है। धामी सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार करके पहाड़ी जिलों में सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने पर खास जोर दिया। चारधाम सड़क परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और ग्रामीण सड़कों की मरम्मत इस दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में नए मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों का उन्नयन और डॉक्टरों की नियुक्तियाँ जनता के लिए बड़ी राहत साबित हुईं। शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रयोगशालाएँ और दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं।

### संवेदनशीलता और तत्परता का संयोजन

उत्तराखण्ड की भौगोलिक संवेदनशीलता को देखते हुए धामी सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत किया। SDRF की क्षमता और संसाधनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। संवेदनशील क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए, जिससे कई स्थानों पर समय रहते चेतावनी देकर नुकसान को कम किया गया। सरकार की प्रतिक्रिया तेज़, मानवीय और पारदर्शी रही यह बात आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों ने साबित की।

### पलायन रोकने की दिशा में प्रयास

उत्तराखण्ड का सबसे बड़ा दर्द पलायन। धामी सरकार ने इसे केवल समस्या नहीं, बल्कि सुधार का अवसर माना। गाँवों में रोजगार देने वाले उद्योगों, कृषि आधारित नवाचारों और होमस्टे योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में लोग वापस अपने गाँवों की ओर लौटते दिखाई दे रहे हैं। इन तीन वर्षों में उत्तराखण्ड ने सुशासन, विकास और निर्णय क्षमता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरकार ने समस्याओं को टालने के बजाय उनका सामना करने की नीति अपनाई। युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ, महिलाओं का सम्मान बढ़ा, धार्मिक स्थलों को नई पहचान मिली, आपदा प्रबंधन बेहतर हुआ और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की शुरूआत हुई। धामी सरकार के ये तीन वर्ष यह संदेश देते हैं कि अगर इच्छाशक्ति हो, तो पहाड़ भी रास्ता बना देते हैं।

# नक्सली माओवाद गिनता अंतिम सांसें

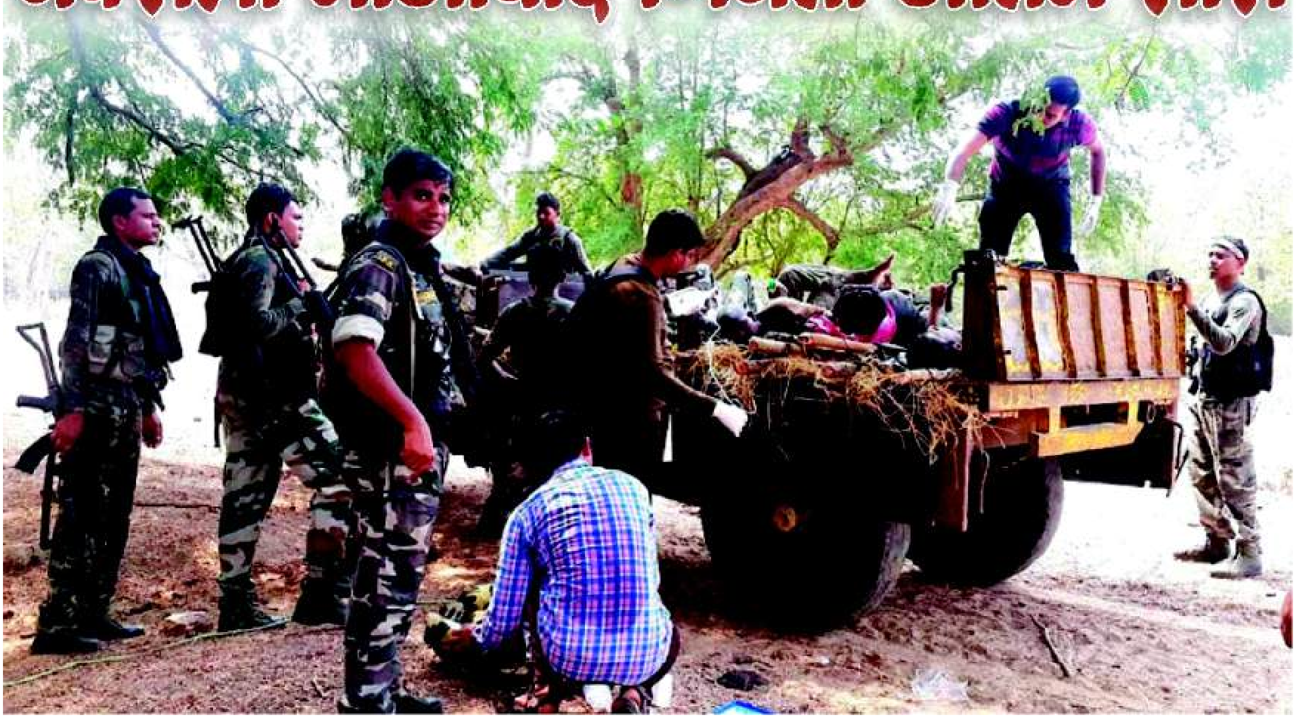

**प्रमोद भार्गव**

छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश की सीमा पर हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने शीर्ष माओवादी क्रूर हिंसा के प्रतीक बन चुके हिड़मा को मार गिराने के बाद सात अन्य नक्सलियों को मार गिराने के साथ तय है, कि अब नक्सली हिंसा अपने अंतिम चरण में है। मार्च 2026 तक इसका समूल नाश हो जाएगा, क्योंकि अब प्रमुख नक्सली सरगनाओं की गिनती मात्र 3-4 तक सिमट गई है। यदि वे हथियार डालकर समर्पण नहीं करते हैं तो उनका भी अंत होना तय है। हालांकि इस मुठभेड़ में मप्र के बालाघाट में पदस्थ निरीक्षक आशीष शर्मा को बलिदान देना पड़ा है। माओवादी अर्से से देश में एक ऐसी जहरीली विचारधारा रही है, जिसे नगरीय बौद्धिकों का समर्थन मिलता रहा है। ये बौद्धिक नक्सली संगठनों को आदिवासी समाज का हितचिंतक मानते रहे हैं, जबकि जो आदिवासी नक्सलियों के विरोध में रहे, उन्हें इनकी हिंसक क्रूरता का शिकार होना पड़ा है। बावजूद इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि देश के वामपंथी दलों को कभी भी सुरक्षाबलों का नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा सफाये का अभियान पसंद नहीं आया। इससे पहले छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता तब मिली थी, जब डेढ़ करोड़ के इनामी बसव राजू समेत 27 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। यह कुख्यात दरिंदा होने के साथ गुरिल्ला लड़ाका था। माओवादी पार्टी का इसे पर्याय माना जाता था। इसका नक्सली सफर 1985 से शुरू हुआ था। इसने वारंगल के क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की थी।

नक्सली हिंसा लंबे समय से देश के अनेक प्रांतों में आंतरिक मुसीबत बनी हुई है। वामपंथी माओवादी उग्रवाद कभी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता रहा है। लेकिन चाहे जहां रक्तपात की नदियां बहाने वाले इस उग्रवाद पर लगभग नियंत्रण किया जा चुका है। नई रणनीति के अंतर्गत अब सरकार की कोशिश है कि सीआरपीएफ की तैनाती उन सब अज्ञात क्षेत्रों में कर दी जाएं जहां नक्सली अभी भी ठिकाना बनाए हुए हैं। इस नाते केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 4000 से अधिक सैन्यबल तैनात करने जा रहा है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि 31 मार्च 2026 तक इस क्षेत्र को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाए। इतनी बड़ी संख्या में सैन्यबलों

की अज्ञात क्षेत्र में पहुंच का मतलब है कि अब इस उग्रवाद से अंतिम लड़ाई होने वाली है। मजबूत और कठोर कार्य योजना को अमल में लाने का ही नतीजा है कि इस साल सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 2024 में 153 नक्सली मारे जा चुके हैं। 2004.14 की तुलना में 2014 से 2024 के दौरान देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी आई है। 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा की 16,274 वारदातें दर्ज की गई थीं, जबकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 सालों में इन नक्सली तंत्र कमजोर हुआ है, लेकिन उसकी शक्ति अभी षेश है। अब तक पुलिस व गुप्तचर एजेंसियां इनका सुराग लगाने में नाकाम होती रही थीं, लेकिन नक्सलियों पर षिकंजा कसने के बाद से इनको भी सूचनाएं मिलने लगी हैं। इसी का नतीजा है कि सैन्यबल इन्हें निशाना बनाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नक्सली आदिवासी हैं। इनका कार्यक्षेत्र वह आदिवासी बहुल इलाके हैं, जिनमें ये खुद आकर नक्सली बने हैं। इसलिए इनका सुराग सुरक्षाबलों को लगा पाना मुश्किल है, विरोध की मुहिम जारी रहनी चाहिए। सरकारें इस समस्या के निदान के लिए बातचीत के लिए भी आगे आईं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इन्हें बंदूक के जरिए भी काबू में लेने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन नतीजे पूरी तरह अनुकूल नहीं रहे। एक उपाय यह भी हुआ कि जो नक्सली आदिवासी समर्पण कर मुख्यधारा में आ गए थे, उन्हें बंदूकें देकर नक्सलियों के विरूद्ध खड़ा करने की रणनीति भी अपनाई गई। इस उपाय में खून खराबा तो बहुत हुआ, लेकिन समस्या बनी रही। गोया,

घटनाओं की संख्या घटकर 7,696 रह गई। इसी अनुपात में देश में माओवादी हिंसा के कारण होने वाली मौतों की संख्या 2004 से 2014 में 6,568 थीं, जो पिछले दस साल में घटकर 1990 रह गई है और अब सरकार ने जो नया संकल्प लिया हैए उससे तय है कि जल्द ही इस समस्या को निर्मूल कर दिया जाएगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आतंक और अलगाववाद खत्म करने की निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, वैसी ही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में अनुभव होने लगी है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में होता है। लेकिन ये इसी आदिवासी तंत्र से बने मुखबिरों से सूचनाएं आसानी से हासिल कर लेते हैं। दुर्गम जंगली क्षेत्रों के मार्गों में छिपने के स्थलों और जल स्रोतों से भी ये खूब परिचित हैं। इसलिए ये और इनकी शक्ति लंबे समय से यहीं के खाद-पानी से पोषित होती रही है। हालांकि अब इनके हमलों में कमी आई है। दरअसल इन वनवासियों में अर्बन माओवादी नक्सलियों ने यह भ्रम फैला दिया था कि सरकार उनके जंगल, जमीन और जल-स्रोत उद्योगपतियों को सौंपकर उन्हें बेदखल करने में लगी है, इसलिए यह सिलसिला जब तक थमता नहीं आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने से लेकर विकास योजनाएं भी इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अब तक सफल नहीं हो पाई हैं।

इस मुठभेड़ में मारे गए हिड़मा का बस्तर के इस जंगली क्षेत्र में बोलबाला रहा है। वह सरकार और सुरक्षाबलों को लगातार चुनौती दे रहा था, जबकि राज्य एवं केंद्र सरकार के पास मोदी सरकार से पहले रणनीति और दृढ़ इच्छाशक्ति की हमेशा कमी रही थी। तथाकथित शहरी माओवादी बौद्धिकों के दबाव में भी मनमोहन सिंह सरकार रही। इस कारण भी इस समस्या का

हल दूर की कौड़ी बना रहा। यही वजह थी कि नक्सली क्षेत्र में जब भी कोई विकास कार्य या चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती थी तो नक्सली उसमें रोड़ा अटका देते थे। अब हिड़मा के मारे जाने के बाद नक्सली समस्या का हल की गुंजाईश बढ़ गई है।

कांग्रेस की पूर्व केंद्र तथा छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार नक्सली समस्या से निपटने के लिए दावा कर करती रही हैं कि विकास इस समस्या का निदान है। यदि तत्कालीन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के विकास संबंधी विज्ञापनों में दिए जा रहे आंकड़ों पर भरोसा करें तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर विकास के मानदण्डों को छूती दिख रही है, लेकिन इस अनुपात में यह दावा बेमानी है कि समस्या पर अंकुश विकास की धारा से लग रहा है, क्योंकि इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को नक्सली बनाए जाने के प्रमाण भी मिले थे। बावजूद कांग्रेस के इन्हीं नक्सली क्षेत्रों से ज्यादा विधायक जीतकर आते रहे थे। हालांकि नक्सलियों ने कांग्रेस पर 2013 में बड़ा हमला बोलकर लगभग उसका सफाया कर दिया था। कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा ने नक्सलियों के विरूद्ध सलवा जुडूम को 2005 में खड़ा किया था। सबसे पहले बीजापुर जिले के ही कुर्तु विकासखण्ड के आदिवासी ग्राम अंबेली के लोग नक्सलियों के खिलाफ खड़े होने लगे थे। नतीजतन नक्सलियों की महेंद्र कर्मा से दुश्मनी ठन गई थी। इस हमले में महेंद्र कर्मा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और हरिप्रसाद समेत एक दर्जन नेता मारे गए थे। लेकिन कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी खोई शक्ति फिर से हासिल कर ली थी, बावजूद नक्सलियों पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपदस्थ कर भाजपा फिर सत्ता में आई, उसके बाद से ही नक्सलियों के सफाए का सिलसिला चल रहा है। दरअसल, देश में अब तक तथाकथित शहरी बुद्धिजीवियों का एक तबका ऐसा भी रहा, जो माओवादी हिंसा को सही ठहराकर संवैधानिक लोकतंत्र को मुखर चुनौती देकर नक्सलियों का हिमायती बना हुआ था। यह न केवल उनको वैचारिक खुराक देकर उन्हें उकसाने का काम करता था, बल्कि उनके लिए धन और हथियार जुटाने के माध्यम भी खोला था। बावजूद इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब ये राष्ट्रघाती बुद्धिजीवी पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किए गए तो बौद्धिकों और वकीलों के एक गुट ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभाव में लेने की कोशिश की थी और गिरफ्तारियों को गलत ठहराया था। माओवादी किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो भी उनके खिलाफ जाता है, उसकी बोलती बंद कर दी जाती हैं। लेकिन अब इस चरमपंथ पर पूर्ण अंकुश लगने जा रहा है।

# विकास बनाम विषमता

रघु ठाकुर

भारत सरकार कुछ दिनों से अपनी पीठ थपथपा रही है और देश की आर्थिक तरक्की के आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, जिसमें:

● भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रही है।

● पिछले 11 वर्षों में भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से उपर आये हैं।

● अमेरिका के द्वारा टैरिफ दरों में वृद्धि के बाद भारत की अर्थव्यवस्था अप्रभावित रही है।

वैसे तो आज के प्रधानमंत्री जब जो जहां जरूरत होती है, वैसे आंकड़ा गढ़ लेते हैं। परंतु इन तीन प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण जरूरी है। निसंदेह अगर बजट की राशि पर निर्धारित करें तो भारत की अर्थव्यवस्था जापान के आगे नजर आयेगी। परंतु अगर इस राशि का आमजन के बीच बंटवारा और देश के भीतर आदमी-आदमी के बीच के अंतर को देखा जाये तो सरकार का दावा अतार्किक लगता है। क्योंकि यह भी एक तथ्य है कि प्रति व्यक्ति औसत आय की गणना में भारत के प्रति व्यक्ति की औसत आय, दुनिया के 142 देशों के बाद 143वें नंबर पर है। यह अर्थव्यवस्था का कैसा विकास है कि बजटीय राशि याने जीडीपी के आंकड़ों में भारत चौथे नंबर पर है परंतु व्यक्तिगत आय में 143वें नंबर पर है। दरअसल अर्थव्यवस्था के विकास का निर्धारण यह होना चाहिये कि देश के प्रति व्यक्ति की औसत आय बढ़े और विषमता कम हो।

**जीडीपी के आंकड़ों में भारत चौथे नंबर पर है परंतु व्यक्तिगत आय में 143वें नंबर पर है। दरअसल अर्थव्यवस्था के विकास का निर्धारण यह होना चाहिये कि देश के प्रति व्यक्ति की औसत आय बढ़े और विषमता कम हो।**

दूसरा कथन सरकार का यह है कि 27 करोड़ देश के लोगों को गरीबी की सीमा से उपर उठाया है। अगर सरकार की गणना में एक व्यक्ति का तात्पर्य एक परिवार के मुखिया से है तो फिर इसका मतलब होता है कि लगभग 100 करोड़ से अधिक गरीबी की सीमा रेखा से उपर आ चुके हैं। परंतु स्वतः सरकार के अनुसार 95 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो सरकार की रियायतों और प्रधानमंत्री की बोली में कहा जाये तो रेवड़ियों का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें 85 करोड़ लोग 5 किलो ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह मुफ्त अनाज लेने वाले हैं। और 10 करोड़ से अधिक अन्य लाभ यथा लाड़ली बहिना लखपति दीदी आदि। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने पिछले सरकार की तुलना में कोई विकास नहीं किया। मैं मानता हूँ कि सरकार की योजनाओं से देश के एक हिस्से को लाभ पहुँचा है। ग्रामीण रोजगार, प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से स्वरोजगार के लिये सरकार द्वारा खोले गये हैं और यह योजना विशेषतः

**सरकार के अनुसार 95 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो सरकार की रियायतों और प्रधानमंत्री की बोली में कहा जाये तो रेवड़ियों का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें 85 करोड़ लोग 5 किलो ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह मुफ्त अनाज लेने वाले हैं। और 10 करोड़ से अधिक अन्य लाभ यथा लाड़ली बहिना लखपति दीदी आदि।**

ग्रामीण महिलाओं के लिये बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई है। गाँव-गाँव में कुछ एक महिलायें और युवा इन ग्रामीण स्वरोजगार केंद्रों से प्रशिक्षित होकर गांवों में अपने घरों के पास स्वरोजगार कर रहे हैं और यह उन्हें एक बड़ा सहयोग है, इस योजना से बच्चियों की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ा है। ग्रामीण स्तर पर स्वसहायता समूह की शुरूआत तो वैसे 80-90 के दशक में बांग्लादेश में मो. यूनुस ने की थी। बाद में दुनिया के अन्य देशों ने उसे अपनाया। निसंदेह यह योजना भारत में भी ग्रामीण रोजगार पैदा कर रही है और ग्रामीण समाज के लिये आजीविका के लिये लाभप्रद सिद्ध हुई है।

वैसे भी हमारे समाज की खानपान, रहन-सहन और जीवनशैली में जो सांस्कृतिक बदलाव आ रहे हैं। उनने तथा परिवारों के विघटन और नये प्रकार के संयोजन ने नये व्यवसायों को गति दी है। आम लोगों के लिये यह व्यवसाय मध्यमवर्गीय संपन्नता और कभी-कभी उच्चवर्गीय संपन्नता की श्रेणी में ला रहे हैं। जैसे खानपान, होटल रेस्त्रा आदि का चलन तेजी से बढ़ा है और स्थिति यह है कि, संपन्न और अमीर तबका आमतौर पर सप्ताह में 2-3 दिन और मध्यमवर्गीय तबका 1-2 दिन घरों पर खाने की बजाय बाहर होटलों पर खाते हैं। इसी प्रकार रोजगार के लिये गांव से पलायन और शहरों में आवागमन के

कारण भी कई करोड़ की आबादी खान-पान के लिये होटलों पर निर्भर है। उच्च मध्यमवर्गीय और मध्यमवर्गीय समाज के लिये यह होटलों में खाना उनकी संपन्नता का पर्याय है और गरीबों के लिये लाचारी, परंतु इससे इंकार नहीं कर सकते हैं कि यह होटल और ढाबा कल्चर संस्कृति अब बढ़ते-बढ़ते कस्बों और गांव तक पहुंच रही है। अब यह भी रोजगार करोड़ों लोगों को आमदनी का जरिया है। परंतु जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि ये रोजगार बढ़े हैं मध्यमवर्ग की संख्या भी बढ़ी है परंतु आय विषमता उससे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है।

भारत में जहां प्रति व्यक्ति औसत आय 2.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष है, वहीं जापान जो आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर से घटकर पांचवें नंबर पर पहुँच गया है, क्योंकि जापान की जीडीपी लगभग 32 लाख करोड़ रूपये की है और भारत की लगभग 33 लाख करोड़ रूपये, परंतु जापान के प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय 29 लाख है और भारत की 2.50 लाख रूपया। जर्मनी की साढ़े सैंतालीस लाख रु पये और अमेरिका की 76 लाख रूपया प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय है। इसलिये आंकड़ों के खेल हाथी के दाँत के समान दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। विकास का पैमाना जीडीपी को मानना, अमानवीय पैमाना है। वास्तव में पैमाना तो व्यक्ति की आय का होता है और होना भी चाहिये। देश के 105 करोड़ लोग मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह अमीरी का पैमाना नहीं माना जा सकता।

आज से 40 वर्ष पहले जब मोबाइल तकनीक आई थी तब मोबाइल होना अति संपन्नता की निशानी थी। आज 5 किलो सरकारी अनाज लेने वाले के हाथ में भी

मोबाइल है बल्कि इस मोबाइल के फैलाव के लिये विकास के बजाय एक प्रकार की तकनीक के नशे का विकास मानना चाहिये। इसका एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारत में विषमता तेजी से बढ़ी है। एक तरफ उन अमीरों की संख्या बढ़ी है जो औसतन ढाई सौ से तीन सौ करोड़ रूपये रोज कमा रहे हैं। और दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति आय आज भी मुश्किल से 10 हजार रूपये के आसपास है। इसलिये विषमता को कम करना और आमदनी के अंतर को कम करना यह कसौटी होना चाहिये। परंतु बाजार की ताकतों ने अपने प्रचार के माध्यम से एक नया दर्शन दिया है यूज एंड थ्रो जो भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है। भारतीय संस्कृति उपयोग, संरक्षण और पुनः उपयोग की रही है जबकि कारपोरेट की संस्कृति उपयोग-दोहन और विनाश की। इस बदलाव से बाजार को लूटने-तिजोड़ी भरने और अपनी संपन्नता बढ़ाने का एक अनंत रास्ता मिल गया है। पहले घर के कपड़े की एक जोड़ी, किताबें, रसोई के बर्तन, कई-कई पीढ़ी चलते थे, यानि जब तक की वे उपयोग होते होते स्वतः समाप्त न हो जायें, तब तक चलते थे।

अब एक व्यक्ति साल में औसतन 10-20 जोड़ी कपड़े बदल लेता है। जरा भी क्षति होने पर उसे फेंक देता है, शिक्षा की किताबें प्रतिवर्ष बदल जाती है। दवाईयां, कृषि आदि की आयु सीमा तय कर दी गई है, जिसके बाद वे स्वतः अप्रभावी हो जायेगी। अब सेल्फ टरमेंनेटर बीज आया है, जो अपने आप नष्ट हो जायेगा। देश के पैमाने पर देखें तो खरबों रूपयों की ऐलोपैथी दवाईयाँ अपने आप काल बाह्य हो रही हैं। अगर विषमता को मिटाना है तो बाजार की अनंत लूट पर बंदिश लगानी होगी। यह कानून मात्र से नहीं बल्कि इसमें एक सामाजिक पहल की भी जरूरत होगी।

**हमें यूज एंड थ्रो के बजाय यूज-रीयूज-अमेंड एंड यूज्य की संस्कृति को बढ़ाना होगा।**

तीसरी बात, जो अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने का कोई प्रभाव नहीं हुआ है यह सरकारी झूठ है। अनेक उद्योगों के क्षेत्र कठिनाईयों में हैं, जो होना स्वाभाविक भी था। मैं इसे अकेले भारत सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ बल्कि अमेरिका आर्थिक साम्राज्यवाद का हमला मानता हूँ। इसका वस्तुपरक आंकलन निकट भविष्य में होगा। अभी हम अपने देश के साथ हैं और रहेंगे, बस इतनी अपील सरकार से करेंगे कि बड़बोलेपन से हालात नहीं बदलते।

# कट्टरपंथी आतंकवाद और माओवादियों का आंतरिक गठजोड़ उजागर

# कुछ राजनेताओं का समर्थन आश्चर्यजनक...?

**रमेश शर्मा**

दिल्ली के लालकिला क्षेत्र में हुये विस्फोट और छत्तीसगढ़ में कुख्यात नक्सली हिड़मा के एनकाउंटर के बाद घटे घटनाक्रम से कट्टरपंथी आतंकवाद और माओवादियों के बीच आंतरिक गठबन्धन तो उजागर हुआ है। वहीं क्रूरतम षड्यंत्रों पर परदा डालने केलिये कुछ राजनेताओं की राजनीति भी आश्चर्यजनक है। हिंसा, आतंकवाद, सामूहिक नरसंहार और क्रूरतम यातनाएँ देकर भारत का सामाजिक-साँस्कृतिक रूपांतरण करने का षड्यंत्र पुराना है। इसमें अनेक शक्तियाँ

> **छत्तीसगढ़ में कुख्यात नक्सली हिड़मा के एनकाउंटर के बाद घटे घटनाक्रम से कट्टरपंथी आतंकवाद और माओवादियों के बीच आंतरिक गठबन्धन तो उजागर हुआ है। वहीं क्रूरतम षड्यंत्रों पर परदा डालने केलिये कुछ राजनेताओं की राजनीति भी आश्चर्यजनक है।**

सक्रिय हैं। बाहर से देखने में तो इनके नाम, रंग रूप, पहनावा और कार्यशैली अलग दिखती है। कोई स्वयं को कट्टरपंथी धर्म समर्थक जेहादी कहे या धर्म विरोधी माओवादी लेकिन भारत विरोधी गतिविधियों में सबके तार एक दूसरे से जुड़े लगते हैं। मानों इन सबका संचालन किसी एक सूत्र से हो रहा हो। लेकिन भारत के कुछ राजनैतिक दलों से संबंधित नेताओं द्वारा इनके समर्थन और संरक्षण के लिये खुलकर सामने आना आश्चर्यजनक इसकी झलक समय समय पर सामने आती रही है। इसकी झलक एक बार फिर

हाल ही देश में घटे दो बड़े घटनाक्रमों में देखने को मिली। पहली घटना दिल्ली के लालकिला क्षेत्र में हुये विस्फोट के बाद आतंकवादियों के सामने आये नेटवर्क की है और दूसरी घटना सुदूर छत्तीसगढ़ में कुख्यात नक्सली हिड़मा के एनकाउंटर की है। इन दोनों घटनाओं ने यह आंतरिक गठजोड़ और उनके समर्थकों के चेहरे एक बार फिर उजागर किये हैं। पुलिस एनकाउंटर में मारे गये कुख्यात नक्सली हिड़मा के समर्थन में भी ठीक उसी प्रकार नारे लगे जैसे वर्ष 2016 में आतंकवादी अफज़ल के समर्थन में लगे थे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने इन दिनों नक्सलवाद को समाप्त करने का अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के अंतर्गत पिछले दिनों कुख्यात नक्सली हिड़मा मारा गया। हिड़मा साधारण नहीं था। वह नक्सली कमांडर था। उसके नेतृत्व में अनेक नक्सली हिंसक समूह सक्रिय थे। छै राज्यों की पुलिस उसे ढूँढ रही थी। अलग अलग राज्यों ने उसकी तलाश के लिये जो पुरस्कार राशि घोषित की थी वह भी लगभग एक करोड़ अस्सी लाख रूपये होती है। इस पुरस्कार राशि से ही उसके क्रूरतम और खूंखार रहने का अनुमान लगाया जा सकता है। अकेले छत्तीसगढ़ में हिड़मा पर दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। अकेले एर्राबोर क्षेत्र में डेढ़ सौ से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या करने का आरोपी था। इसमें सुरक्षा बल के जवानों की संख्या अस्सी से अधिक है। इसके अतिरिक्त आसिरगुड़ा, चिंतागुफा, कासलपाड़, बुरकापाल, मिनपा, टेकलगुड्म और पिडमेल आदि स्थानों में घात लगाकर सुरक्षाबलों पर किये गये हमलों और अधिक निर्मम हत्याओं के पीछे नक्सली हिड़मा का नाम आता है। ऐसे दुर्दांत हत्यारे के समर्थन में भारत के तीन अलग अलग स्थानों से आवाज सुनी गई। सबसे पहले छत्तीसगढ़ से एक वीडियो जारी हुआ। इस वीडियो को देशभर में सोशल मीडिया पर फैलाया गया। इसे नक्सल समर्थक महिला सोनी सोढ़ी ने तैयार किया था जिसमें हिड़मा की मौत को एनकाउंटर नहीं हत्या बताया गया। वीडियो में कोर्ट जाने की बात भी कही है। नक्सली हिड़मा के एनकाउंटर से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के नक्सल विरोधी अभियान पर प्रश्न खड़े कर चुके थे। उन्होंने अभियान को आदिवासी पर हमले निरूपित किया था। लेकिन जो नारा दिल्ली में सुना गया उसने नक्सलवाद को कट्टरपंथी आतंकवाद से तार जुड़े होने को

एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर इन दिनों एक प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन तो प्रदूषण पर है लेकिन इसमें नारे हिड़मा के समर्थन में लगे। एक नारा था- तुम कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा। यह नारा ठीक वैसा ही है जैसा वर्ष 2016 में कुख्यात आतंकवादी अफ्जल की बरसी पर लगे था। उस नारे में कहा गया था- तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। इसके अतिरिक्त और भी देश विरोधी नारे लगे थे। अब नौ वर्ष बाद हिड़मा के लिये भी ठीक उसी प्रकार नारा लगा। इसमें शब्द और शैली वही है जो अफजल के समर्थन में थी। केवल नाम का अंतर आया है। कहने के लिये मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकवाद और माओवाद दोनों अलग अलग धारायें हैं। एक अपने धर्म के

**एक नारा था- तुम कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा। यह नारा ठीक वैसा ही है जैसा वर्ष 2016 में कुख्यात आतंकवादी अफ्जल की बरसी पर लगे था। उस नारे में कहा गया था- तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा।**

लिये कट्टर है तो दूसरा धर्म विरोधी नास्तिक। वैचारिक दृष्टि से इनमें कोई मेल नहीं है। लेकिन भारत के सांस्कृतिक स्वरूप पर हमला करने के लिये दोनों के बीच गहरा गठबंधन है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि आतंकवादी अफजल को फाँसी मिलने की बरसी उस जेएनयू में मनाई गई थी जो माक्सवाद और माओवाद का वैचारिक केन्द्र माना जाता है। तब भी यह प्रश्न उठा था कि कट्टरपंथी जेहादियों और माओवाद के बीच कितना गहरा गठजोड़ है। जो अब हिड़मा के एनकाउंटर के बाद पुनः दोनों का आंतरिक गठजोड़ स्पष्ट हुआ।

**आतंकवाद समर्थक राजनीति**

एक ओर भारत विरोधी विभिन्न शक्तियाँ

एकजुट होकर हिंसा और आतंक के नये नये तरीके अपना रहीं हैं वहीं कुछ राजनैतिक दलों के नेताओं का समर्थन भी आश्चर्यजनक है। हिड़मा एनकाउंटर पर काँग्रेस पार्टी से संबंधित दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के वक्तव्य सामने आये तो दिल्ली के लालकिला क्षेत्र में हुये आतंकी विस्फोट में काँग्रेस के तीन नेताओं के ऐसे वक्तव्य आये जिनमें इन आतंकवादियों के प्रति सद्भाव की स्पष्ट झलक है। यह विस्फोट भारत में आतंकवाद की कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी दिल्ली सहित भारत के विभिन्न नगरों और महत्वपूर्ण स्थलों पर विस्फोट हुये हैं लेकिन यह घटना साधारण नहीं थी। इससे जुड़े आतंकवादी न तो सीमापार से आये थे और न उन्होंने किसी निर्जन क्षेत्र में बने अड्डे में आतंकवाद का प्रशिक्षण लिया था। यह सब महानगरों में रहने वाले उच्च शिक्षित युवा हैं। विश्वविद्यालय परिसर इनकी गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र था। इनका नेटवर्क पन्द्रह राज्यों में फैला है और पाकिस्तान, सउदी अरब, तुर्की और हमास आदि से भी नेटवर्क जुड़ा हैं। वे ड्रोन से हमला करने और हिन्दू धार्मिक स्थलों के पानी में जहर मिलाकर लाखों लोगों को मार डालने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तारियों में अनेक चौंकाने वाले विवरण सामने आये हैं। फिर भी काँग्रेस से जुड़े नेता उनके समर्थन में दिखे। पहला वक्तव्य काँग्रेस नेता श्री राशिद अल्वी का आया। उन्होंने प्रश्न उठाया कि आखिर किस मजबूरी में ये हिंसा की राह पकड़ रहे हैं। वो पढ़ा-लिखा नौजवान जिसने एमबीबीएस और एमडी किया है, वह आतंक का रास्ता क्यों अपनाएगा? इसपर मोदीजी विचार करें। दूसरा वक्तव्य कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का आया। उन्होंने विस्फोट में शामिल लोगों को गुमराह बताया था। यह भाषा शैली वही है जैसी कश्मीर के आतंकवाद पर पर्दा डालने केलिये कुछ नेताओं ने भटके हुये नौजवान बताया था। इन दो वक्तव्यों से एक कदम आगे जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का आया। उन्होंने दिल्ली में घटी इस आतंकवादी घटना के बाद हुई गिरफ्तारियों को मुसलमानों से जोड़ा और कयी प्रश्न खड़े किये। उनके बयान का समर्थन करने में कांग्रेस नेता उदित राज ने देर नहीं की और सुरक्षा बलों की धरपकड़ को उत्पीड़न की श्रेणी में माना। एक ओर क्रूरतम हिंसकों का गठजोड़ जहाँ भारत की प्रकृति ही नहीं उसके साँस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप केलिये नई नई चुनौतियाँ खड़ी कर रहा है वहीं दूसरी ओर कुछ राजनैतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा केवल राजनीति केलिये ऐसे वक्तव्य देना अपने आप में एक चिंताजनक और विचारणीय बिन्दु है। ये वक्तव्य उनकी तुष्टीकरण की राजनीति के तो उपयुक्तहो सकते हैं लेकिन ये राष्ट्र नीति के विरुद्ध ही माने जायेंगे।

# भोपाल गैस त्रासदी: समस्या से समाधान तक

**विजया पाठक**

मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसम्बर सन् 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 8000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस काण्ड में मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) नामक ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ था। मध्यप्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3787 लोगों की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8000 लोगों की मौत तो दो सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गये थे। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 5,58,125 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी। 3900 तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गये।

**त्रासदी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभावों के जख्म अभी भी भरे नहीं हैं। हालांकि, कचरा हटाने का कार्य हुआ है, गैस के संपर्क में आए लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं (जैसे श्वसन संबंधी बीमारियाँ) अभी भी मौजूद हैं। केवल कचरा उठाने से गैस पीड़ितों के साथ न्याय नहीं हुआ है।**

**कचरा उठा लेकिन जख्म अभी भरे नहीं**

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से हुए गैस

कांड के बाद 358 मीट्रिक टन कचरा 40 साल बाद 1 जनवरी 2025 को भोपाल से निकालकर इंदौर के पास पीथमपुर लेकर गए। 12 कंटेनर, 250 किमी लंबे ग्रीन कॉरिडोर और भारी सुरक्षा बल लेकर जब जहरीला कचरा पीथमपुर के रामकी एनवायरो इंडस्ट्रीज पहुंचा तो कई सवाल उठ खड़े हुए आम जनता में दहशत फैलने लगी। गैस रिसाव से उत्पन्न जहरीले कचरे को तो हटा दिया गया है, लेकिन इस त्रासदी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और सामाजिक आवश्यकता है, जो अब तक नहीं मिला है। कचरा हटाने का काम भले ही हो गया हो, लेकिन कचरे से जुड़ी अन्य समस्याएं जैसे कि पर्यावरण की सफाई और प्रभावित लोगों की दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ अभी भी अनसुलझी हैं। यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकले 12 ट्रक जहरीले कचरे को पीथमपुर ले जाया गया था। इस तरह दुर्घटना के बाद का भौतिक कचरा हटा दिया गया। गैस त्रासदी के 41 साल बाद, जहरीले कचरे से निकली राख एक नई मुसीबत बन प्रक्रिया खत्म हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन यह राख अभी भी लीक-प्रुफ डिब्बों में एक शेड के अंदर रखी हुई है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पक्का इरादा दिखाया और इस डेवलपमेंट का विरोध कर रहे लोगों को मनाने में कामयाब रही और ज़हरीले कचरे को आखिरकार कई स्टेप्स में जला दिया गया। अब, राज्य सरकार के सामने एक और समस्या है और वह यह है कि यूनियन कार्बाइड प्लांट के

प्रभावों के जख्म अभी भी भरे नहीं हैं। हालांकि, कचरा हटाने का कार्य हुआ है, गैस के संपर्क में आए लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं (जैसे श्वसन संबंधी बीमारियाँ) अभी भी मौजूद हैं। केवल कचरा उठाने से गैस पीड़ितों के साथ न्याय नहीं हुआ है, क्योंकि यह समस्या का एक छोटा सा हिस्सा है और न्याय की मांग अभी भी जारी है। न्याय के लिए पर्याप्त मुआवजा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और स्थायी पुनर्वास की गई है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सामने 899 टन राख को ठिकाने लगाने की चुनौती है। यह राख यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकले कचरे को जलाने से बनी है। इस साल मई और जून में, पीथमपुर के एक ट्रीटमेंट प्लांट में 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा जलाया गया था। इस प्रक्रिया से 899 मीट्रिक टन राख और अवशेष निकले, जो मूल कचरे से लगभग तीन गुना ज्यादा थे। 55 दिन तक चली यह भस्मीकरण 358 टन केमिकल कचरे को जलाने के बाद निकली लगभग 900 टन बची हुई राख का क्या किया जाए। यह चुनौती तब और बड़ी हो गई जब इस साल अक्टूबर की शुरुआत में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ज़हरीली राख को स्टोर करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस वजह से, लगभग 900 मीट्रिक टन बची हुई राख अभी भी एक प्राइवेट फैक्ट्री के कंटेनरों में पड़ी है, जहाँ यूनियन कार्बाइड का ज़हरीला

कचरा जलाया गया था। राज्य सरकार को अब ज़हरीली राख को खत्म करने और समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने का कोई दूसरा तरीका खोजना होगा। राज्य सरकार कोई दूसरा समाधान खोजने पर विचार कर रही है और इसे हाई कोर्ट के सामने मंजूरी के लिए लाया जा सकता है।

**पीड़ितों के इलाज और पुनर्वास की स्थिति बेहद खराब**

मौजूदा शासन में भोपाल गैस पीड़ितों के इलाज और आर्थिक मदद की स्थिति काफी गिर गई है। 2008 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने लंबे समय के पुनर्वास के लिए एक विशेष आयोग बनाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोक दिया। उनका कहना है कि इस फैसले का असर आज भी साफ दिखता है। बहुत से प्रभावित परिवार अब तक ठीक इलाज और आर्थिक सहारे से वंचित हैं, और अगली पीढ़ी भी इन कठिनाइयों का सामना कर रही है। गैस त्रासदी के बाद चार दशक बीत चुके हैं। लेकिन यह हादसा अब भी शहर के लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। 42 बस्तियों का पानी ऐसे कैमिकल से प्रभावित है, जो जन्मजात विकृतियां पैदा करते हैं। ये रसायन कैंसर, गुर्दे और मस्तिष्क रोगों का कारण बनते आए हैं। प्रभावित इलाके में रह रहे लोगों ने बताया कि उनके बच्चे मानसिक तौर पर कमजोर पैदा हो रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ फैक्ट्री परिसर की जमीन पर वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले यहां की मिट्टी की गुणवत्ता के परीक्षण की भी मांग उठ रही है। यूनियन कार्बाइड के आसपास 3 किमी का भूजल दूषित हो चुका है। ऐसे में इसे साफ करना बड़ी चुनौती है। पर्यावरणविद, गैस पीड़ित और जानकार यहां हरियाली के पक्ष में खड़े नजर आए। पर्यावरणविदों का कहना है कि परिसर और आसपास के इलाके की जमीन जहरीली है। इसलिए इसका रासायनिक परीक्षण होना चाहिए। इसके बाद इस इलाके को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला जाना चाहिए।

**क्यों कचरा उठाना न्याय नहीं है?**

**अपर्याप्त मुआवजा:** पीड़ितों को दिया गया मुआवजा मुद्रास्फीति के हिसाब से अपर्याप्त है और कई लोगों ने तो वह राशि भी नहीं ली क्योंकि फॉर्म भरना जटिल था।

**स्वास्थ्य समस्याएं:** गैस त्रासदी से प्रभावित लाखों लोगों को आज भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए पर्याप्त इलाज उपलब्ध नहीं है।

**पर्यावरणीय क्षतिः** कचरे को हटाना एक छोटी सी सफलता है, लेकिन गैस रिसाव से प्रदूषित हुई मिट्टी और पानी की सफाई अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

**कॉर्पोरेट जिम्मेदारी:** यूनियन कार्बाइड और डाउ जैसी कंपनियों पर कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी तय करने में कई बाधाएँ आईं और उन्हें पूरी तरह से जवाबदेह नहीं ठहराया गया है।

### कचरा उठाने के बाद की स्थिति

**कचरा निपटान का विरोध:** कचरे को हटाना एक सराहनीय कदम है, लेकिन जिस तरह से इसे निपटाया जा रहा है, उस पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह उनके इलाके में प्रदूषण बढ़ाएगा।

**भविष्य की चिंताएँ:** कचरा हटाने के बाद भी, कुछ लोगों को डर है कि भविष्य में इस कचरे का जहरीला असर फिर से उभर सकता है।

कचरा उठाना भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक छोटा सा कदम मात्र है। असली न्याय के लिए इन सभी मुद्दों फैक्टरी अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन (UCC) की सहायक थी, जो 50.9 प्रतिशत हिस्सेदार थी। भारत सरकार UCC की 22 प्रतिशत साझेदार थी।

**मुआवजे की शुरूआत:** 470 मिलियन डॉलर का समझौता, जो अपर्याप्त साबित हुआ। 1989 में भारत सरकार और छक्क के बीच सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता से 470 मिलियन डॉलर (तब 715 करोड़ रूपये) का समझौता हुआ। यह पूर्ण और अंतिम था। सरकार ने इसे 5,000 करोड़ रूपये का बताया, लेकिन वास्तव में यह कम था। प्रति मृतक 62,000 रूपये, घायल को 25,000-50,000 रूपये। लेकिन मौतें 3,787 बताई गईं, जबकि वास्तविक 15,000+ थीं।

**वितरण:** भोपाल गैस त्रासदी राहत विभाग ने 5.7 लाख दावों पर 1,549 करोड़ (मूल)+1,517 करोड़ वितरित किए। मुद्रास्फीति के हिसाब से आज यह 4,000 करोड़ हो जाती। पीतों को पर्याप्त नहीं मिला। कई ने 5,000 रूपये भी नहीं लिए, क्योंकि फॉर्म भरना मुश्किल था। 2001 में डाउ केमिकल ने UCC को खरीदा। डाउ ने कहा, सभी दावे सेटल हो चुके। लेकिन पीड़ितों का कहना है कि डाउ जिम्मेदार है, क्योंकि UCC की देनदारी उसके पास आई।

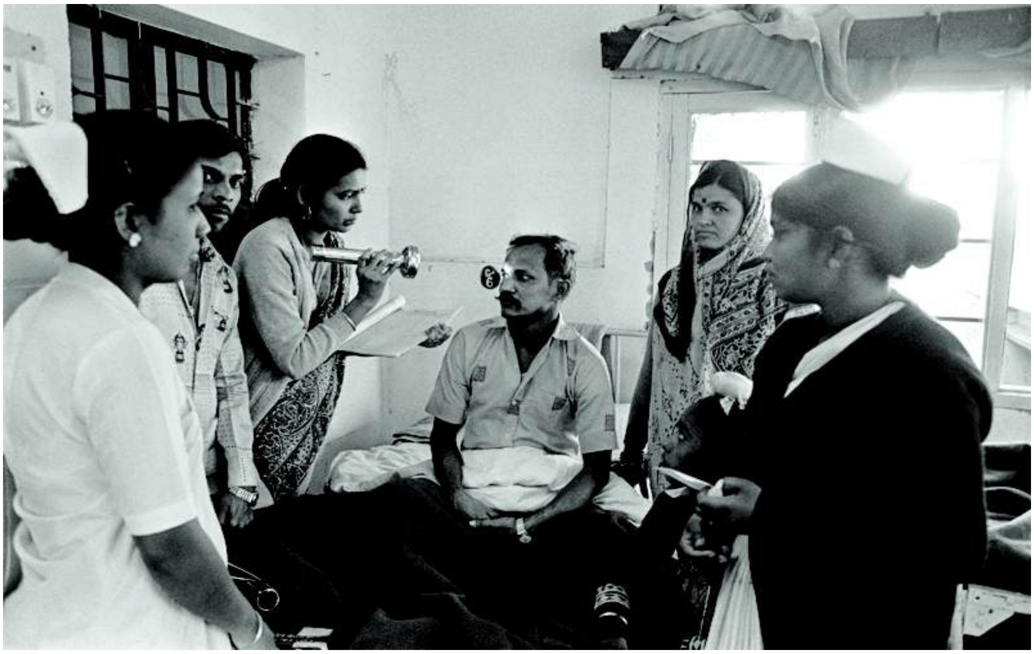

### त्रासदी का कारण और घटनाक्रम

**क्या हुआ:** यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने के एक टैंक में पानी घुसने के कारण दबाव बना और सेफ्टी वाल्व फट गया, जिससे भारी मात्रा में जहरीली MIC गैस हवा में फैल गई।

**तत्काल प्रभाव:** गैस से भोपाल की सड़के लाशों से भर गई. हजारों लोग आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के साथ अस्पतालों में पहुंचे।

आधिकारिक और अनुमानित मौतें: शुरु आती सरकारी आंकड़े 2,259 मौतें बताते हैं, लेकिन विभिन्न स्रोतों के अनुसार, कुछ हफ्तों में 8,000 से अधिक और अगले दो दशकों में 15,000 से 20,000 और मौतें हुई।

**प्रभावित लोग:** 5 लाख से ज्यादा लोग गैस के संपर्क में आए, जिनमें से कई विकलांग हो गए, अंधेपन का शिकार हुए और गंभीर बीमारियों से जूझते रहे।

### दीर्घकालिक परिणाम और चुनौतियाँ

**पर्यावरण प्रदूषण:** गैस रिसाव से जमीन, पानी और ठोस पदार्थों में जहरीले तत्व मिल गए, जो आज भी मौजूद हैं।

**स्वास्थ्य प्रभाव:** गैस के संपर्क में आने से कई तरह की बीमारियाँ हुई, और कई उजागर व्यक्तिभोपाल छोड़कर चले गए, जिससे वास्तविक संख्या का पता लगाना मुश्किल हो गया।

**न्यायिक लड़ाई:** त्रासदी से जुड़े कई मामले दशकों बाद भी लंबित हैं, और मुआवजे के लिए संघर्ष जारी है। 1989 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, पीड़ितों को पर्याप्त न्याय और मुआवजा नहीं मिल पाया है।

# 25 years of Jharkhand - who gained, who lost ?

**FP Desk**

On the occasion of Jharkhand's 25th anniversary, we are writing to say how disappointed we are with your work, and to appeal to you to mend your ways.

The creation of Jharkhand was the culmination of a long struggle. Public-spirited persons from all communities played a leading role in this movement. Many have sacrificed their lives for it. Their dream was that the creation of Jharkhand would enable the adivasis-moolvasis of this area to develop according to their own values values of freedom, equality, friendship and harmony with nature. Jharkhand's independence was also supposed to put an end to exploitation from

outsiders.

Twenty-five years later, the dream has turned sour. No doubt, most people in Jharkhand are better fed, clothed and housed today than they were twenty-five years ago. But millions are still living in grinding poverty. And Jharkhand is not what it was supposed to be. The beautiful civilization of Chhotanagpur and Santhal Parganas is threatened with destruction as powerful companies eye its land, minerals and other natural resources. Jharkhand's free and proud farmers are turning into wage labourers and drifting into dilapidated cities. Soon, there may be little to distinguish Jharkhand from the rest of India, except for it being poorer.

**No doubt, most people in Jharkhand are better fed, clothed and housed today than they were twenty-five years ago. But millions are still living in grinding poverty. And Jharkhand is not what it was supposed to be**

You, Jharkhand's political leaders, bear prime

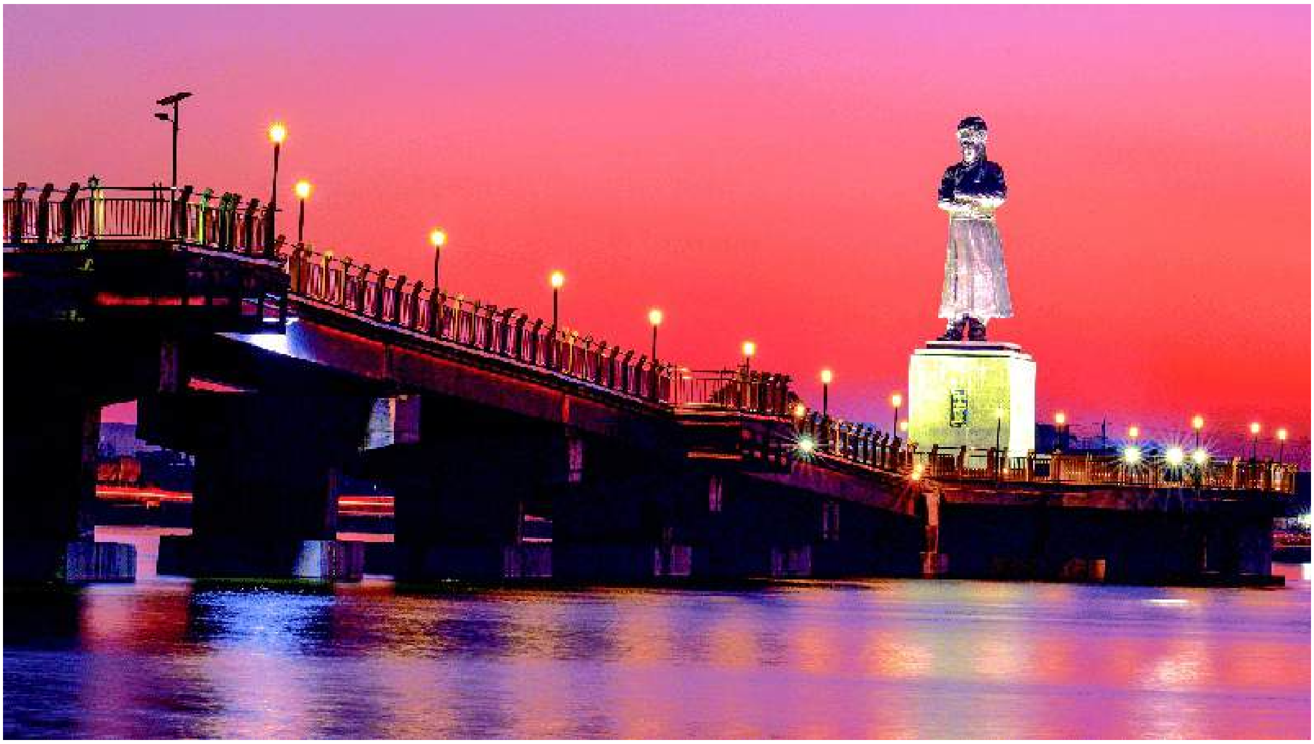

responsibility for this. Instead of emulating the stalwarts of the Jharkhand movement and working for the common people, you have colluded with the exploiters to enrich yourselves. You are selling Jharkhand's rich resources to greedy businesses at the expense of local people. You have allowed the schooling system to go to rack and ruin, forcing lakhs of youngsters to become migrant workers. You have looted NREGA in collusion with corrupt contractors, depriving millions of their right to work. For twenty-five years, you have failed to make rules for PESA. You have allowed gross violations of the CNT-SPT acts and the Forest Rights Act. You have made plenty of money from big infrastructure contracts even as basic facilities like drinking water, drainage and pavements are missing everywhere, even in Ranchi.

Some of you have also divided the people of Jharkhand and incited them

against each other to consolidate your power. "*Dhan naheen, ek sahee*" (unity, not wealth) was one of the popular slogans of the Jharkhand struggle. Today, little remains of this unity. The exploiters have a field day as people fight among themselves.

The outlook is unlikely to improve unless political leaders mend their ways. We already count some of you as our comrades, and we have some hope from others too. But if the political class does not mend its ways, it may face complete rejection from the people. More importantly, we are hoping that a new generation of leaders will emerge, made of women and men who have the interests of the people to heart. For our part, we shall continue to work for change in our own way.

On behalf of the Mahasabha,

Ajay Ekka, Aloka Kujur, Aman Marandi, Afzal Anis, Ambika Yadav, Ambita Kisku, Apurva, Arunanshu Banerji, Ashok Verma, Bharat Bhushan Choudhary, Binsaya Munda, Birsingh Mahto, Charles Murmu, Chandradev Hembrom, Dinesh Muru, Elina Hiro, James Herenj, George Monipalli, Jean Dreze, Jyoti Bahan, Jyoti Kujur, Kumar Chandra Mardi, Lina, Manthan, Manoj Bhuiyan, Mary Hansda, Munni Devi, Mina Murmu, Naresh Pahadia, Pravin Peter, Prem Bablu Soren, P.M. Tony, Puneet Minz, Nand Kishore Gunjhy, Paran, Riya Tulika, Pingua, Raja Bhai, Ranjit Kiro, Ramesh Jerai, Rose XaXa, Rose Madhu Tirkey, Ramesh Malto, Rejina Indwar, Reshmi Devi, Ram Kavindra, Sandeep Pradhan, Sangeeta Beck, Siraj Datta, Shashi Kumar, Santoshi Lakda, Cicilia Lakda, Shankar Malto, Tom Kavla, Timothy Malto, Binod Kumar, Vivek Kumar

# जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

**: विषय :**

**मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)**

## प्रवेश प्रारंभ

**संपर्क सूत्र**

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25
डबल इंजन की सरकार में विकास सुपरफास्ट
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
रावघाट- जगदलपुर रेल परियोजना के साथ रेल नेटवर्क मैप से जुड़ रहा बस्तर
पीएम जनमन योजना के साथ जनजाति समुदाय का हो रहा विकास
दक्षिण छत्तीसगढ़ में बोधघाट परियोजना बनेगी हरियाली और समृद्धि का वरदान
महतारी वंदन से महिलाओं को संबल
किसानों को बकाया बोनस, पीएम किसान सम्मान निधि का भी लाभ
26 लाख से अधिक परिवारों को अपना पक्का आवास
जगदलपुर- विशाखापत्तनम और रायपुर- विशाखापट्टनम नई सड़क परियोजनाओं से विकास की नई राहें
स्पष्ट नीति और मजबूत निर्णयों के साथ सुशासन का राज
हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें
RO. No. 13571/1
/ChhattisgarhCMO
/DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

# सुरक्षा सम्मान स्वाभिमान

## महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई उड़ान

**2025-26 ₹8245 करोड़ का बजट**

महतारी वंदन | पोषण | स्वास्थ्य समृद्धि | ऋण | सुरक्षा

### आर्थिक सशक्तिकरण

**महतारी वंदन योजना**

70 लाख से अधिक महिलाओं को 14,306.33 करोड़ रुपये की सहायता

**मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना**

8000 कन्याओं के विवाह हेतु ₹40 करोड़ का प्रावधान

NRLM के लिये 800 करोड़ का प्रावधान (लखपति-ड्रोन दीदी शामिल)

पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसव के बाद ₹20,000 की आर्थिक सहायता

महिला समूहों को पुनः मिली रेडी टू ईट के कार्य की जिम्मेदारी

### सुरक्षा और संरक्षण

महिला हेल्पलाइन 181 व डायल 112 24x7 आपातकालीन सहायता

सखी वन स्टॉप सेंटर : पीड़ित महिलाओं को तत्काल परामर्श एवं कानूनी सहायता

### सामाजिक बदलाव

हर साल उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिला संगठनों को 'युवा रत्न सम्मान'

महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण

### उद्यमिता और रोजगार

42,878 महिला स्व-सहायता समूहों को आसान ऋण से अब तक ₹129.46 करोड़ का लाभ

उद्यम व्यवसाय केंद्र की स्थापना हेतु ₹108.78 करोड़ की लागत से 368 महतारी सदन के निर्माण को मंजूरी

महिला समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु ₹200 करोड़ की लागत से नवा रायपुर में यूनिटी मॉल प्रस्तावित

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

## नारी की शक्ति

छत्तीसगढ़ की प्रगति

RO. No. 13571/1

संकल्प से सिद्धी की ओर

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in